



SPECIAL BULLETIN

ON

3rd UNIVERSITY LOK ADALAT

on 10th December, 2016 at Jharkhand High Court Premises



INAUGURATION OF 500 LEGAL LITERACY CLUB IN 500 SCHOOLS IN JHARKHAND FOR TRIBAL GIRLS AND BOYS

on 10th December, 2016 from KGBV, Mandar simultaneously

Prepared by

Jharkhand State Legal Services Authority

Nyaya Sadan, Near A.G. Office, Doranda, Ranchi

Phone : 0651-2481520, 2482392, Fax : 0651-2482397

Email : jhalsaranchi@gmail.com, Website : www.jhalsa.org

This Special Bulletin is also available on official website of JHALSA "www.jhalsa.org"



MENDIAGNOSA SEBAGAI LEGAL SEPTEN
SECURITY'S LEGAL REFORMS
IN THE NCIOSIS S CO

3RD UNIVERSITY LOK ADALAT

on 10th December, 2016



GENESIS OF THE PROGRAMME

“Lok Adalat is a pathway for social engineering which has to be activated by helping those who are in a problem. We are committed to provide them relief.”

-Justice Dipak Misra

The aforesaid golden words of His Lordship Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra is a source of inspiration for all the legal fraternity. His Lordship has further said that “Some may feel it's a small case, but the person who has to appear in the court knows how big the case is for him. It is in this context that Mega Lok Adalats are held to solve the matter amicably.”

The benefits of Lok Adalats are immense. Every year lakhs of cases pending in the Court as well as Pre-litigation matters are disposed of through Lok Adalats.

There are six universities in the State of Jharkhand namely : Ranchi University Ranchi, Vinoba Bhave University Hazaribagh, Nilamber-Pitamber University Daltonganj, Kolhan University Chaibasa, Sido-Kanhu Murmu University Dumka & Birsa Agriculture University, Ranchi.

First University Lok Adalats was organized in the Country on 13th May, 2012 at Nyaya Sadan, JHALSA, Ranchi for the Court pending as well as pre-litigation matters of the teaching & non-teaching employees of the Universities of the State of Jharkhand and as many as 131 cases were disposed of and an amount of Rs. 3.85 crores were disbursed.

Within 10 days the Second University Lok Adalat was organized at Nyaya Sadan, JHALSA, Ranchi on huge demand of the teaching and non-teaching staffs of the Universities and 130 matters were disposed of and 2.49 crores rupees were disbursed amongst the beneficiaries.

The exercise for Third University Lok Adalat began on 23rd June, 2016 with the blessings of Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Hon'ble Governor & Chancellor of the Universities of Jharkhand.

PREPARATIONS

that made 3rd University Lok Adalat Phenomenon Success

It took six month's hard work and a series of high level meeting to achieve the kind of result that was seen on the 10th of december 2016. His Lordship Hon'ble Mr. Justice D.N.Patel, Executive Chairman, JHALSA, worked tirelessly for 6 month (June'16-Dec'16). Here are the glimpses of 6 months journey to historic success of Mega Event.

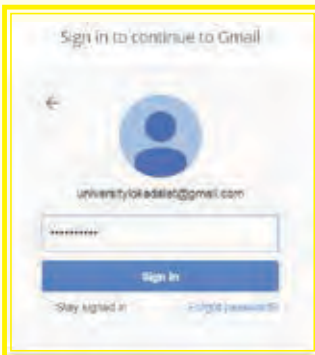
MEETING WITH HON'BLE GOVERNER ON 23TH JUNE 2016 AT RAJBHAWAN



Seen in the picture are Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand, Hon'ble Executive Chairman, JHALSA and University Officers including Vice-Chancellors.



OPENING OF EMAIL ACCOUNT ON 28TH JUNE, 2016 DEDICATED EXCLUSIVELY FOR UNIVERSITY LOK ADALAT (universitylokadalat@gmail.com)



Seen in the picture are Dr. Neera Yadav, Hon'ble Minister, Human Resource Development Deptt. Govt. of Jharkhand, Hon'ble Executive Chairman, JHALSA and Government Secretaries & University Officers.



MEETING WITH HON'BLE HRD MINISTER & SECRETARIES OF HIGHER & TECHNICAL DEPARTMENT, FINANCE DEPARTMENT AT JHALSA ON 23TH JULY 2016



MEETING WITH HON'BLE GOVERNER ON 18TH OCTOBER 2016 AT RAJBHAWAN



Seen in the picture are Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand, Dr. Neera Yadav, Hon'ble Minister, Human Resource Development Deptt. Govt. of Jharkhand, Hon'ble Executive Chairman, JHALSA, Smt. Raj Bala Verma, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Sri Amit Khare, Addl. Chief Secretary cum Pr. Secretary, Planning and Finance, Govt. of Jharkhand, Sri Binod Poddar, Advocate General, Addl. Advocates Generals, University Officers including the Vice-Chancellors.

MEETING WITH CHIEF SECRETARY, DGP, HOME SECRETARY, ADVOCATE GENERAL, SECRETARIES OF HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION & OTHER DEPARTMENTS, LEARNED COUNSELS FOR UNIVERSITIES OF JHARKHAND AND UNIVERSITY OFFICIALS AT JHARKHAND HIGH COURT ON 29.11.2016



Seen in the picture are Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Executive Chairman, JHALSA, Smt. Raj Bala Verma, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Sri N.N. Pandey, Addl. Chief Secretary cum Pr. Secretary, Home Department, Govt. of Jharkhand, Sri D.K. Pandey, DGP, Jharkhand, Sri A.K. Singh, Secretary, Higher and Technical Education (in the left picture), Sri A.K. Rai, Member Secretary, JHALSA and Sri Manish Ranjan, Director, Secondary Education (in the right picture)

पांच को होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग

जब, राष्ठी : लोकतंत्र सिटोई बलव खोलने को लेकर भ्रमालवह को छत्रछाड राई कोर्ट के न्यायाधीश सह जलमको के कार्यकारी अध्यक्ष खोल पटेल की अध्यक्षता में पदाधिकारियों को बैठक हुई। इसमें पांच दिवसको को कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में 500 विद्यार्थियों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया।

राष्ठीनत राष्ठी विद्यालय में आनतपुत्र सुविधा शुरूवा करने, दस दिवसको को आयोजित कार्यक्रम को लेखन खतवक व अधिवेशियों की मुका पर विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

जलमवह अदालत कोर्ट परिसर के विचारविमर्श में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मिलेगी निजात

राष्ठीनत राष्ठी विद्यालय में आनतपुत्र सुविधा शुरूवा करने, दस दिवसको को आयोजित कार्यक्रम को लेखन खतवक व अधिवेशियों की मुका पर विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

जलमवह अदालत कोर्ट परिसर के विचारविमर्श में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

स्कूली बच्चे हासिल करेंगे कानूनी ज्ञान

जलमवह अदालत कोर्ट परिसर के विचारविमर्श में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

जलमवह अदालत कोर्ट परिसर के विचारविमर्श में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। अधिवेशियों को बतलाया गया कि कानूनवा गणेश बलमवह विद्यालय माह में तीन बच्चे लोकतंत्र सिटोई बलव का उदघाटन शुरू करने में आनतपुत्र किया जाना है। राई कोर्ट परिसर में वृत्तिसिंह लोक अदालत आयोजित

VISIT OF HIS LORDSHIP HON'BLE EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA TO KASTURBA GANDHI BALIKA VIDYALAYA MANDAR FOR SEE PREPARATION FOR INAUGURATION OF LEGAL LITERACY CLUB IN 500 SCHOOLS ON 05.12.2016.

जस्टिस डीएन पटेल ने लिया तैयारियों का जायजा

जागरण संवाददाता, रांची/मांडर : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लीगल लिटरेसी क्लब के आयोजन को लेकर विभिन्न जिलों में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। वह मुख्य आयोजन स्थल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से अन्य जिलों के साथ ऑनलाइन जुड़े थे। 10 दिसंबर को क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन मांडर से होना है।

विभिन्न जिलों में चल रही तैयारियों पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ ही आठ दिसंबर तक पूरी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने क्लब वाले कमरे का निरीक्षण किया। इसमें उपलब्ध संसाधनों पर संतोष व्यक्त करते हुए कानून से जुड़ी सभी पुस्तकों, पंपलेटों आदि को करीने से सजाने का निर्देश दिया। वह पानी, बिजली, शौचालय, पाकशाला, सुरक्षा आदि की बारीकियों से भी रूबरू हुए। जस्टिस ने विद्यालय प्रशासन से भी कमियों से संबंधित सुझाव मांगा, ताकि समय रहते सुधार लाया जा सके। जस्टिस ने कस्तूरबा की छात्राओं द्वारा बैच का नेहरू प्रदर्शन की मुरीद हुए। उन्होंने प्रदर्शन को देख प्रसन्नता जाहिर करते हुए छात्राओं को धन्यवाद

♦ न्यायिक पदाधिकारियों ने किया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर का निरीक्षण

♦ 10 दिसंबर को विभिन्न जिलों में ऑनलाइन खुलेंगे लीगल लिटरेसी क्लब



मांडर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निरीक्षण करते झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल, झालसा सचिव एके राय व अन्य।

किया। छात्राओं को नए छात्रावास में शिफ्ट किए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया। सभी न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर को राज्य के 500 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का

ऑनलाइन उद्घाटन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से किया जाना है। निरीक्षण में रजिस्ट्रार जनरल एके चौधरी, प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के सदस्य सचिव एके राय, डिप्टी सेक्रेटरी सत्यकांत प्रियदर्शी, झारखंड हाई

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता आज

रांची : लीगल लिटरेसी क्लब को लेकर मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्कूल परिसर में मौलिक कर्तव्य विषय पर राज्यस्तरीय निबंध व चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में झालसा के सदस्य सचिव एके राय व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.एमएस पाठक करेंगे। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अच्युतानंद ठाकुर स्वागत व जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।

कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनीष रंजन, उपायुक्त मनोज कुमार, ग्रामीण एस्प्री राजकुमार लकड़, जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर व अन्य लोग मौजूद थे।

VISIT OF HIS LORDSHIP HON'BLE EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA TO KASTURBA GANDHI BALIKA VIDYALAYA MANDAR FOR SEE PREPARATION FOR INAUGURATION OF LEGAL LITERACY CLUB IN 500 SCHOOLS ON 08.12.2016.

पहल : कस्तूरबा विद्यालय मांडर से होगा आगाज, 500 विद्यालयों में होगी क्लब की ऑनलाइन शुरुआत

लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन कल

जागरण संवाददाता, रांची/मांडर : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से राज्य के 203 कस्तूरबा सहित 500 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन जनिवार को किया जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट परिसर में तृतीय यूनिवर्सिटी लोक अदालत का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुकृवर की ज्ञान रांची पहुंचेंगे।

उधर, क्लब के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने गुरुवार को तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों से तैयारियों के बारे में पूछताछ की। साथ ही छोटी-छोटी कमियों को सुक्रवार तक दूर करने का निर्देश दिया। क्लब की शुरुआत को लेकर जस्टिस पटेल का यह तीसरा निरीक्षण था। उन्होंने शिक्षा विभाग व प्रशासन के अधिकारियों से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की।

निरीक्षण के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रत्नकर भंगरा, झारखंड राज्य विधिक सेवा



मांडर में लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनलाइन जायजा लेते जस्टिस डीएन पटेल व अन्य।

प्राधिकार (झालसा) के सदस्य सचिव एके राय, प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार, झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी सत्यकांत प्रियदर्शी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनीष रंजन, परियोजना निदेशक मुक्ता कुमार, ग्रामीण एस्प्री राजकुमार लकड़, क्षेत्रीय शिक्षा

उप निदेशक अच्युतानंद ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर, जिला शिक्षा अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार, झालसा के पैनल अधिकारिता कैलाश गोप, पीएलवी सुमन ठाकुर, बबली कुमारी सहित अन्य न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे।

राज्यपाल व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे मुख्य अतिथि

लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपा मिश्रा मौजूद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री लुइस मरांडी, शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति के साथ-साथ झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायाधीश एवसी मिश्रा सहित अन्य न्यायाधीश व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विचारियों के बीच पूर्व में 'मौलिक कर्तव्य' विषय पर आयोजित विस्फुटा एवं निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

GLIMPSES OF 3RD UNIVERSITY LOK ADALAT ON 10.12.2016 AT JHARKHAND HIGH COURT



Arrival & Welcome of Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor of Jharkhand



Arrival & Welcome of **Sri Raghubar Das**, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand



Arrival & Welcome of Hon'ble Mr. **Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India



Arrival & Welcome of Hon'ble Mrs. **Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India



Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor of Jharkhand inaugurating the programme by lighting of lamp



Sri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand inaugurating the programme by lighting of lamp



Hon'ble Mr. **Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India inaugurating the programme by lighting of lamp



Hon'ble Mrs. **Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India inaugurating the programme by lighting of lamp



Seen in the picture are Hon'ble Mr. **Justice D.N. Patel**, Executive Chairman, JHALSA welcoming the Hon'ble Dignitaries. (From L to R) : Hon'ble Mr. **Justice H.C. Mishra**, Judge, High Court of Jharkhand, **Dr. Neera Yadav**, Hon'ble Minister, Human Resource Development Deptt., Govt. of Jharkhand, Hon'ble Mrs. **Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India, **Sri Raghubar Das**, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand, Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor of Jharkhand, Hon'ble Mr. **Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India & Hon'ble Mr. **Justice P.K. Mohanty**, Acting Chief Justice, High Court of Jharkhand cum Patron-in-Chief, JHALSA



Seen in the picture are Madam Poonam Mishra, Madam Suprama Misra, Madam Kalpana Mohanty, Madam Giraben D. Patel, Madam Sweety Topno, Madam Sanchita Das, Madam Vandana Singh, Hon'ble Dignitaries and participants in the 3rd University Lok Adalat

SPEECHES OF HON'BLE DIGNITARIES**HER EXCELLENCY SMT. DROUPADI MURMU, HON'BLE GOVERNOR OF JHARKHAND**

- मैं इस लोक अदालत के लिए, इस अवसर के लिए, आप सभी तथा झालसा के चेयरमैन जस्टिस डी.एन. पटेल साहब को शुभकामना देती हूँ।
- आज का यह दिवस अत्यंत ऐतिहासिक एवं उल्लासकारी है। प्रसन्नता का विषय है की 5000 से ज्यादा लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त होने को है और उनकी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। मैं पुनः झालसा को बधाई देती हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री तथा विभिन्न विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय के उपकुलपति को भी बधाई देती हूँ। आप सबों के अथक प्रयास से इस लोक अदालत का सफल आयोजन संभव हो सका है।
- निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश दीपक मिश्रा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती आर. भानुमति का मार्गदर्शन झालसा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अतः शीघ्र न्याय प्रदान कराने के लिए तत्परता से काम करने की जरूरत है।
- जनहित एवं त्वरित निर्णय लेने की दिशा में लोक अदालत एक अहम् एवं सार्थक प्रयास है। दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर फैसला होता है।
- हमारे देश के न्यायिक प्रणाली की यह प्रक्रिया पूरे विश्व की न्यायिक प्रक्रिया में लोकप्रिय है। आपसी सहमति से लिया गया फैसला दोनों पक्षों को अपार खुशी प्रदान करता है।
- राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में हमारा प्रयास रहा है कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक



समय-समय पर होती रही है। इसी क्रम में विभिन्न डेलीगेशन्स के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हमारे विश्वविद्यालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों की विभिन्न मांगों वर्षों से कोर्ट में लंबित हैं। सबको उनका हक शीघ्र मिले इसलिए विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक कई बार आहूत की गई जिसके लिए राज्य की शिक्षा विभाग तथा जस्टिस डी.एन. पटेल बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने लोक अदालत के आयोजन के प्रति अपनी गहरी रूचि दिखाते हुए सक्रियता के साथ कार्य किया।

- चांसलर होने के नाते मेरे लिए हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय के 5000 से ज्यादा सदस्यों को अपने बकाया के भुगतान हेतु कोर्ट नहीं जाना पड़ा और झालसा के माध्यम से यह संभव हो पाया।
- मैं विश्वास व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही विशेष लोक अदालत मिशन मोड के तहत प्राइमरी मिडिल एवं हाई स्कूल के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तथा सरकार के अन्य विभागों के लिए भी लगाया जायेगा।
- सरकार को परिस्थितिवश सबसे बड़ा लिटिगेंट बनना पड़ता है चूँकि सरकार का दायित्व भी सबसे बड़ा है। हम यह संकल्प करें कि लाल फीता शाही आम जन को शीघ्र एवं सुगम न्याय के रास्ते में बाधक नहीं बनने देंगे।
- शासन की सार्थकता इस बात से होती है कि न्याय सुलभ, शीघ्र तथा सस्ती हो तथा लोक अदालत इसी उद्देश्य पर काम करता है।
- आप सभी से अनुरोध है कि लोक अदालत को आंदोलन का रूप देकर दूर-दूरस्थ एवं ग्रामीण इलाकों में लगाया जाये और झारखंड की जनता को उनके हक की जानकारी देते हुए न्याय उनके द्वार तक पहुँचाया जाये।
- न्याय लोगों को उनके द्वार पर मिले इसमें झालसा का योगदान अहम है और इसमें राज्य सरकार झालसा के कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर रहे। मेरा सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SRI RAGHUBAR DAS, HON'BLE CHIEF MINISTER, JHARKHAND

- झालसा के चेयरमैन श्री डी0 एन0 पटेल जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने झालसा के माध्यम से, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो या सामान्य जनता हो, जो न्याय के लिए भटक रहे थे उन्हें झालसा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं ।
- आज भी जो झालसा के माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है उसमें लाभान्वित होने वाले विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी हैं ।
- हम सभी जानते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं अन्य मामलों में जो समस्याएँ हैं वह विरासत में मिले हैं जिसके कारण उच्चतम न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय में भी मामले लंबित हैं और इस लंबित मामलों में भी अधिकांश मामले वेतन एवं बकाया वेतन को लेकर हैं और इस लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन हेतु झालसा का प्रयास सराहनीय है ।
- झालसा एवं राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है कि आज लोक अदालत के माध्यम से 4910 शिक्षको एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच 113 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत के माध्यम से अनेक यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर आज नियुक्ति-पत्र भी दी जा रही है ।
- मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो सारी समस्याएँ हैं वह सरकार के द्वारा स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण हैं । ये सारे मामले न्यायालय में जाते हैं और इसलिए सरकार गठन के बाद से ही हमारी सरकार पॉलिसी मैटर पर फोकस की है ।
- सरकार के खिलाफ मुकदमें दायर किये जाते हैं और इसका कारण है कि स्पष्ट नीति नहीं है ।
- न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए । गरीब से गरीब व्यक्ति की न्याय तक पहुँच होनी चाहिए ।
- हम राँची को, जो राज्य की राजधानी है, उसको ज्ञान की राजधानी बनाना चाहते हैं और हमें अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ज्यादा प्रेरित करना है । यह हमारे सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबी को नेस्तानवुद करने का औजार शिक्षा है । मैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा साहब तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमती भानुमती साहिबा का झारखंड की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ । झालसा के साथ सरकार हमेशा है और रहेगी ।



HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA, JUDGE, SUPREME COURT OF INDIA

- It is a momentous occasion, I have not come here to witness any kind of record. But, it pleases me the most to be here. I am delighted to be here. 2500 year back a philosopher asked a Judge, then Judge, in different sense, what is the greatest virtue on this earth? He said – Justice. Justice is the greatest virtue. Because Justice is the queen of all virtues. Justice is mother of all virtues.
- Duty of Justice is to wipe away tears of the poor, socially marginalized and people who are in difficulty.
- Today in this Lok Adalat the cases which would have come before the Courts because of the grievances pertaining to pension, or dues in matters of services, have been settled. The cases which are pending in the Court have been settled by the Universities with the help of the government.
- When a case is settled, there is no Victor, there is no winner, there is no prize, there is no humiliation. On the contrary, there is humility, there is comity, there is amiability, there is relationship and there is social relationship.
- I have come here today to see the settlement of cases and the tears from the eyes of poors being wipedout. To see how they feel. To witness that feeling of the employees, the aggrieved people without judicial adjudication. I have come here only for that. That is why I am here and not for any record.
- We have three rights- social rights, political rights and economic rights. This trilogy of rights is the strength of constitution.
- The Executive, Legislature and Judiciary have a role- a separate role. This role is to work as per the constitution.
- We have an ADR policy. Under Section 89 of the CPC, there are so many methods- Arbitration, Conciliation, Judicial Settlement, Mediation and Lok Adalat. I am not talking about Arbitration, Conciliation and Judicial Settlement for the simple reason that in the Lok Adalat you are going to discuss. You are the Protagonist. You are the participants and the members of the Bar, I emphasise, are the Catalysts. They are the strugglers, they are the fighters in a different way, they make people



arrive at a settlement. Bench and the Bar are allowing the litigants to come to a settlement. The lawyers and the Judges have to facilitate the parties in a Lok Adalat to arrive at a settlement. They have to work as a facilitator.

- We can have a culture of settlement or settlement culture in India. It is the duty of every State Legal Services Authority, every lawyer, every litigant to make an effort seriously to see as to whether matter can be settled. If you can settle the matter, there is nothing good like that. If you cannot settle, you may fight in courts. But first the culture of settlement must grow in India. We cannot be complacent.
- If you can aspire for sky, you can reach the tree. We have reached the tree but still there are further trees to reach, further heights to achieve. You must have heard the great Preacher Lord Budha. Lord Budha's place is not very far away from this place. Lord Budha told us- Follow the middle path. And that is where the Lok Adalat fits in. "Both parties in Lok Adalat must come in joint hands with fair and just solutions and this is the significance of the mechanism.
- A society exists because of gives and takes, live and let live. You cannot say- I will live alone. Nobody on earth can live singularly. People must follow the middle path and to follow the middle path fits in the Lok Adalat.
- I want to emphasise on two aspects- wherever required, the Permanent Lok Adalat must be established as stipulated Under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987. Second one is very important one. Every State must have a positive and concrete litigation policy. I have been told that the States have their litigation policies. Supposing a bunch of litigation is decided by the Apex Court and you think that others are there with similar facts and grievances, then you must not wait for their coming to the courts. It is better you give them the relief. If they are entitled for reliefs, then you must give it to them. This must be a part of the litigation policies, unless the claim is totally barred by limitation.
- State is the biggest litigant in the country in all courts. There has to be a policy as to which type of cases should travel to the High Courts or the Supreme Court. How they do it is for the policy makers to decide. We are not going to tell them how to make it but there must be a litigation policy in place.
- I am thrilled, I am excited, I am delighted to be here. For your patience and silence, thank you.

HON'BLE MRS. JUSTICE R. BANUMATHI, JUDGE, SUPREME COURT OF INDIA

- I am very happy to participate in this Mega Lok Adalat organised by JHALSA for settling the University cases of both teaching non-teaching staff.
- The NALSA had first drawn its National Plan of Action in 2009-10.
- Even though we have Sec. 89 of the CPC but we have this National Plan of Action to render community based Legal Awareness.
- Over the years NALSA has prepared various legal services schemes for Free and competent legal services.
- Now there is a shift in the concept of legal aid that is from the Lawyer based legal services, legal aid to Community based legal services
- When I was the Chief Justice here, we had conducted National Lok Adalat on 23rd of November, 2013. In that 1st National Lok Adalat on 23rd of Nov., 2013, we were able to dispose of more than 1 lakh cases.
- Legal Services has now become an effective mode of delivery of justice, not only in cases which are pending in the Court but in various other social problems.
- The JHALSA, I am proud to say, is marching ahead. It has strengthened the legal services across the State, not only in settling the pending cases but it has taken pre litigation cases to community based area also.
- It is also befitting that we are today releasing the Scheme for **Saving the Girl child** and also the pamphlet & FAQ on NALSA Schemes for legal aid to Senior Citizens and Acid Attack victims.
- JHALSA has also taken initiative today to inaugurate Legal Literacy Clubs in 500 Schools in the State. JHALSA's community based legal services is laudable and are being appreciated by one and all.
- In today's Lok Adalat the grievance of teaching and non-teaching staff of the Universities of Jharkhand are taken up and the areas of such grievances are: non payment of arrears, arrears of 6th pay revision, post retiral dues, compassionate appointment, ACP, non payment of increment, promotion and such other grievance.
- As a Chief Justice I had occasion to see the grievances of teaching and non-teaching staff of Jharkhand.
- Today I was told that It is only because of the efforts taken by JHALSA for more than 6 months and with the intervention of Her Excellency the Governor of Jharkhand and the generous funds allotted by the Govt. by the Hon'ble Chief Minister of Jharkhand and the Education Minister and other concerned Govt. Officials, that this programme has been so much successful.



- We are happy to note that more than Rs. 113 crores are likely to be disposed of today amongst the beneficiaries, which comprises of both teaching and non-teaching staff of Jharkhand.
- It is possible only because of the Intervention of the Governor, who is the Ex-officio Chancellor the University of Jharkhand and I thank all of them. Let's give a big round of applause to all of them
- I would like to make a few suggestions to JHALSA:
 1. There are other areas where JHALSA is required to give attention like Mutation cases, and 138 N.I. Act cases, where pending as well as pre-litigation matters require attention.
 2. There are matrimonial disputes where cases are at litigation as well as pre-litigation stage. These are some of the areas we need to concentrate upon.
- I would like to request to JHALSA that there are many other service cases which are pending in the Hon'ble Court and also there are pre litigation matters. I would request the Advocate General to look into these cases.
- I would request the Chief Minister to issue direction to various department to settle these service matters, which will save both money and judicial time that the matter should be settled in these kind of Lok Adalats.
- I congratulate Justice D.N. Patel for organising this programme.

**HON'BLE MR. JUSTICE P.K. MOHANTY, CHIEF JUSTICE, HIGH COURT OF JHARKHAND
CUM PATRON-IN-CHIEF, JHALSA**

- I welcome you all in this prestigious occasion of 3rd University Lok Adalat being organised by the Jharkhand State Legal Services Authority. It is very pride occasion for JHALSA as more than 5000 teaching and non-teaching employees of the Universities of Jharkhand are going to be benefitted.
- This is the prestigious occasion as the occasion is being witnessed by Her Excellency Smt. Draupadi Murmu, the Governor of Jharkhand and the Chancellor of all the Universities of Jharkhand, Sri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister of Jharkhand and Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge, Supreme Court of India, Dr. Neera Yadav, Hon'ble HRD Minister, Govt. of Jharkhand and the large number of dignitaries from all over the State. This is very rewarding occasion for all and all the beneficiaries who are going to get their long pending dues.
- We are also thankful to the members of the Bar for making the Lok Adalat a great success.
- In addition to this Lok Adalat, regular Lok Adalats are also organised from time to time.



- I personally believe that with the greater cooperation from the public and litigants at large and means of the State, the Lok Adalat will achieve greater success.
- Regular conciliation proceedings are organised by the High Court Legal Services Committee.
- Being Patron-in-Chief of Jharkhand State Legal Services Authority, I express my sincere gratitude to Her Excellency the Governor of Jharkhand for all cooperation without which we could not have organised this mega event.
- I also express my sincere gratitude to Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra who has always been a guide to us for organising such event.
- I also express my sincere gratitude to Hon'ble Chief Minister of Jharkhand and Hon'ble Minister of Human Resource Development Department for their support without which we could not have been able to dispose of so many cases in this Mega Lok Adalat.
- I also express my gratitude to Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge, Supreme Court of India who has always carried a special attachment with Jharkhand.

**DR. NEERA YADAV,
HON'BLE MINISTER HRD DEPT. GOVT. OF JHARKHAND**



- यह एक ऐतिहासिक मेगा लोक अदालत है। इससे पहले दो बार जब विश्वविद्यालय के लिए मेगा लोक अदालत लगाया गया तो डिस्पोजल बहुत छोटा था और आज हम उस लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी।
- आज भी हमें वह दिन याद है जब हम विचार कर रहे थे कि क्या हम 100 करोड़ तक का आंकड़ा छू सकते हैं क्या। आज हमने उस लक्ष्य को छु लिया है इसीलिए मैंने कहा कि यह ऐतिहासिक मेगा लोक अदालत है।
- आप सबों को मालूम ही है कि मैं भी पारा लीगल वॉलन्टियर रह चुकी हूँ सो लोक अदालत को हमने बहुत करीब से देखा है। हमें लगता है कि लोक अदालत लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसमें कई फायदे हैं। हम सबका दायित्व है कि लोगों को लोक अदालत के लिए प्रेरित करें।
- आज हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों

के मन में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि अब उन्हें न्यायालयों और कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और लोक अदालत में ही उन्हें न्याय मिल जायेगा।

- ऐसी व्यवस्था बनाने की हम कोशिश करेंगे कि आपको कोर्ट में जाना ही न पड़े।
- आप शिक्षण एवं पठन-पाठन में पूरी उर्जा लगा दें। आपकी समस्याओं का अब लोक अदालत में ही निराकरण कर दिया जायेगा।
- शिक्षा विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 100 कॉलेज बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। महिला डिग्री कॉलेज 11 जगह बनना शुरू हो गया है। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरूआत कर दी गई है एवं वहां पढ़ाई भी शुरू हो गई है।
- हमारी कोशिश है कि झारखंड में बच्चों को पढ़ाई के लिए झारखंड से बाहर न जाना पड़े।

**HON'BLE MR. JUSTICE D.N. PATEL, JUDGE, HIGH COURT OF JHARKHAND
& EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA**



- I welcome you all in this 3rd University Lok Adalat.
- Today is International Human Rights Day and absolutely humanity is winning in this University Lok Adalat and several good works are going to be done today.
- Both parties will feel that they have won the battle. There shall not be any appeal. It is a cost saving process.
- Sometimes remedy is worse than the disease. King Ashoka had won the Kalinga Battle, but he was not happy. Pandavas won the battle of Mahabharat, but they had to go to Himalayas. I once again welcome all the dignitaries and the participants in this historic 3rd University Lok Adalat.

**HON'BLE MR. JUSTICE H.C. MISHRA,
JUDGE, HIGH COURT OF JHARKHAND**



- Today indeed is a historic day. When on the occasion of International Human Right day this Universities Lok Adalat is being held for teaching and non teaching employees of the Universities of Jharkhand in which we are expecting that more than 5000 persons are going to be benefitted by distribution of cheques of more than 125 crores of rupees. It is indeed a Mega Lok Adalat in all respect.
- Today itself we are going to inaugurate Legal Literacy Club s in more than 500 schools of Jharkhand.
- Indeed we are proud that such Mega Events are taking place for the first time in the country in the State of Jharkhand. As the whole world is observing Human Right Day we could not have the celebrated this day in a better way.
- Her Excellency the Hon'ble Governor Smt. Droupadi Murmu has been an inspiring personality as Chancellor of Universities of the State of Jharkhand. Your excellency this University Lok Adalat could not achieved without your active initiatives. Madam on my own behalf and on behalf

of all legal fraternity I thank you for all the pains taken by you for ensuring the mega success of the Lok Adalat.

- Hon'ble Chief Minister Sri Raghubar Das has been very concerned for all round progress of the State Looking into the importance of this event he postpond his abroad tour I sincerely thank the Hon'ble Chief Minister Sri Raghubar Das.
- My Lord Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India has always been an inspiration behind such event that relates to the settlement of the disputes by ADR methods and Lok Adalats My Lord has always taken pains for quick dispensation of justice to the poor and the needy and in all matters relating to the weaker sections of the society. We all get inspiration from His Lordship that despite His Lordship busy schedule at the Supreme Court, His Lordship finds time for conducting such event in all the parts of the country. I on my behalf and on behalf of all legal fraternity extend our sincere thanks to His Lordship.
- This is like Home coming for Hon'ble Mrs. Justice Banumathi, Judge, Supreme Court of India. We have seen closely the untiring personality of Mrs. Justice Banumathi while she was working as Chief Justice of Jharkhand.
- His Lordship further proposed vote of thanks for Hon'ble Justice P.K. Mohanty, Acting Chief Justice of Jharkhand High Court, Hon'ble HRD Minister Smt. Dr. Neera Yadav, Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Executive Chairman, JHALSA, Hon'ble Judges of Jharkhand, Vice Chancellors of all the Universities and all the dignitaries present.

DISTRIBUTION OF APPOINTMENT LETTERS TO THE BENEFICIARIES

(Total 18 Persons received compassionate appointment letter in the Lok Adalat on 10-12-2016 from the dignitaries)



Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary



Sri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary



Hon'ble **Mr. Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India presenting Appointment Letter to the beneficiary



Hon'ble **Mrs. Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India presenting Appointment Letter to the beneficiary



Hon'ble **Mr. Justice P.K. Mohanty**, Acting Chief Justice, High Court of Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary



Dr. Neera Yadav, Hon'ble Minister HRD Deptt., Govt. of Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary



Hon'ble **Mr. Justice D.N. Patel**, Judge, High Court of Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary



Hon'ble **Mr. Justice H.C. Mishra**, Judge, High Court of Jharkhand presenting Appointment Letter to the beneficiary

CHEQUE DISTRIBUTION IN 3RD UNIVERSITY LOK ADALAT ON 10.12.2016 AT JHARKHAND HIGH COURT
(300 from out of total 5553 Teaching and non-teaching employees of the University of Jharkhand received cheques from the Hon'ble dignitaries) (Total amount distributed in 3rd University Lok Adalat on 10-12-2016 is **Rs. 128,67,30,763**)



Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Hon'ble Governor Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Sri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge, Supreme Court of India presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice P.K. Mohanty, Acting Chief Justice, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Dr. Neera Yadav, Hon'ble Minister HRD Deptt., Govt. of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary

**DISTRIBUTION OF CHEQUE TO THE TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY
IN 3RD UNIVERSITY LOK ADALAT ON 10.12.2016 AT JHARKHAND HIGH COURT**



Hon'ble Mr. Justice Aparesh Singh, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice S. Chandrashekhar, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice Pramath Patnaik, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice Ratnaker Bhengra, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice Ananda Sen, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice S.N. Pathak, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Hon'ble Mr. Justice Rajesh Shankar, Judge, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary



Sri Binod Poddar, Advocate General, High Court of Jharkhand presenting cheque to the beneficiary

3RD UNIVERSITY LOK ADALAT ON 10-12-2016



Hon'ble Dignitaries releasing the JHALSA (Legal Services for Eradication of Female Foeticide Menace and Saving the Girl Child) Scheme, 2016



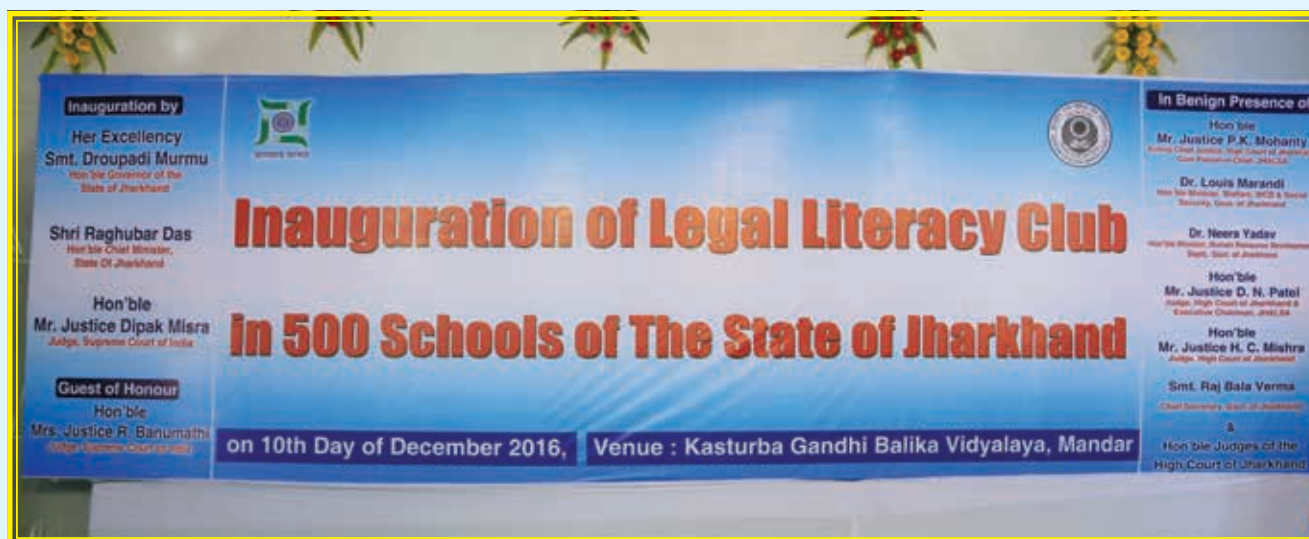
Hon'ble Dignitaries releasing the FAQ & Pamphlet of NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016 & NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016



Hon'ble Dignitaries releasing the JHALSA Diary and Directory

INAUGURATION OF LEGAL LITERACY CLUBS IN 500 SCHOOLS

on 10th December, 2016



GENESIS OF THE PROGRAMME

“Life is a glorious gift from God. It is the perfection of nature, a masterpiece of creation. It is majestic and sublime. Human being is the epitome of the infinite prowess of the divine designer.”

-Justice Dipak Misra

The father of the Nation Mahatma Gandhi had said “If we want to reach real peace in this world, we should start educating children and by education, I mean an all-round drawing of the best in child and man in body, mind and spirit.”

It is the quality education alone that can make the difference in the life of a person and nation. The Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya is a noble concept of quality education to the girl child of scheduled tribes, schedule caste & girls of most marginalized section of the society. It is a residential school with a view to provide an atmosphere for all round development.

There are 203 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in the State of Jharkhand, where meritorious girls are studying. They are the future of our country.

It is truly said that Girls’ education is the single best investment that any society can make. Education of children, especially girls, is the cornerstone to national progress.

The concept of Legal Literacy Club is to impart knowledge of basic laws of the land, fundamental rights & fundamental duties as well as the values and ethics enshrined in our constitution. The girls and boys of our time must know the values and struggle of our freedom fighters and the makers of constitution.

It is the duty of every generation and government to provide its children an atmosphere where they may grow to fullest of their potential.

GLIMPSES OF INAUGURATION OF 500 LEGAL LITERACY CLUBS IN 500 SCHOOLS

in the State of Jharkhand for the Tribal Boys and Girls at a time simultaneously from Kastoorba Gandhi Balika Vidyalaya, Mandar on 10-12-2016



Welcome of Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Hon'ble Governor of Jharkhand by the student of KGBV, Mandar



Welcome of Sri Raghubar Dar, Hon'ble Chief Minister of Jharkhand by the student of KGBV, Mandar



Welcome of Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge Supreme Court of India by the student of KGBV, Mandar



Welcome of Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge Supreme Court of India by the student of KGBV, Mandar



Lighting of Lamp by Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Hon'ble Governor of Jharkhand



Lighting of Lamp by Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge Supreme Court of India



Lighting of Lamp by Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge Supreme Court of India



Lighting of Lamp by Hon'ble Mr. Justice P. K. Mohanty, Acting Chief Justice, High Court of Jharkhand

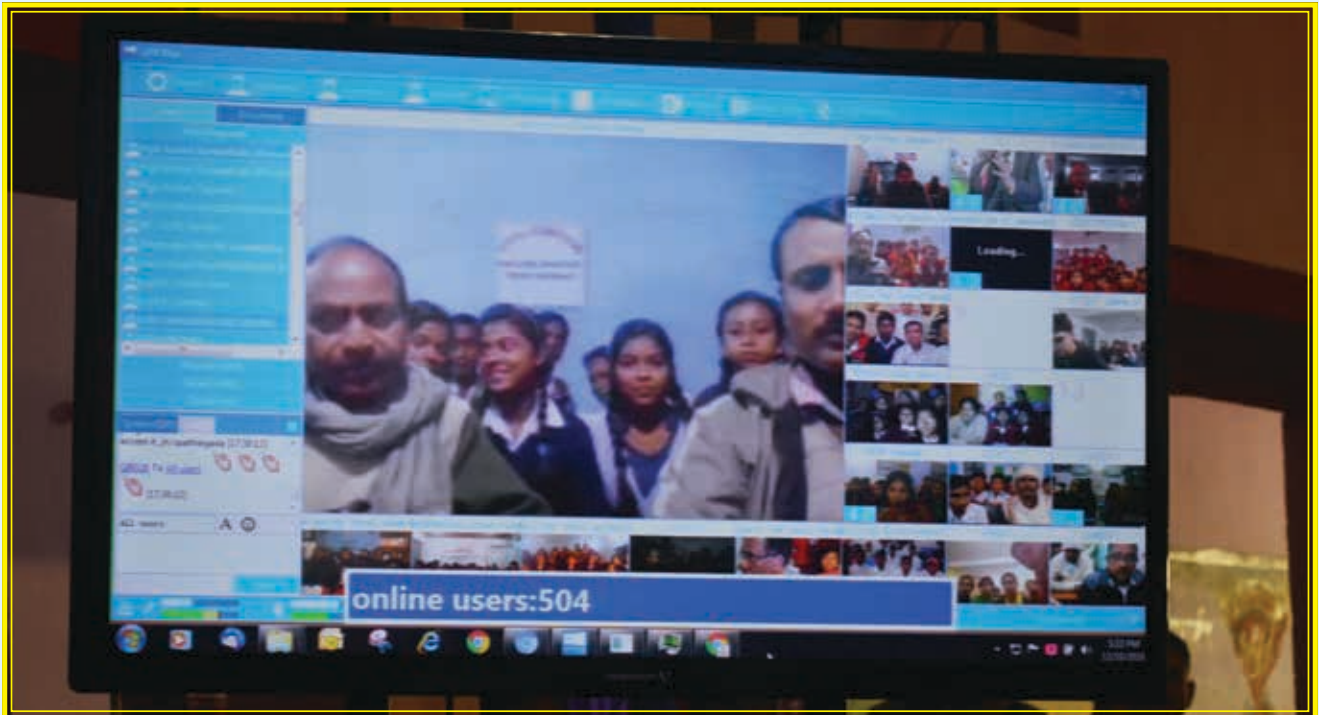
INAUGURATION OF LEGAL LITERACY CLUB AT KASTOORBA GANDHI BALIKA VIDYALAY, MANDAR ON 10-12-2016



Seen in the picture are Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor of Jharkhand, **Sri Raghubar Das**, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand, Hon'ble Mr. **Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Mrs. **Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Mr. **Justice D.N. Patel**, Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA inaugurating the Legal Literacy Club in Kastoorba Gandhi Balika Vidyalaya, Mandar



Seen in the picture are Hon'ble Mr. **Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India inaugurating the Legal Literacy Club in 500 Schools. With his Lordship in this picture is Hon'ble Mr. **Justice D.N. Patel**, Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA



Inauguration of Legal Literacy Clubs in 500 School by Video Conferencing



Seen in the picture are Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor of Jharkhand, **Sri Raghubar Das**, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand, Hon'ble **Mr. Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble **Mrs. Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble **Mr. Justice D.N. Patel**, Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA in the Legal Literacy Club, Kastoomba Gandhi Balika Vidyalaya, Mandar and seeing the books.

SPEECHES OF HON'BLE DIGNITARIES

HER EXCELLENCY SMT. DROUPADI MURMU, HON'BLE GOVERNOR OF JHARKHAND



- शिक्षा के इस मंदिर में जिसको हम कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कहते हैं वहाँ से लिट्रेसी क्लब के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है।
- बच्चों को विधिक जानकारी सुलभ कराने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए झालसा के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री डी.एन. पटेल को बधाई देती हूँ जिनके अथक प्रयास से राज्य के विद्यालयों में लीगल लिट्रेसी क्लब का शुरुआत किया जा रहा है।
- ये हमारे बच्चे ही देश के कर्णधार हैं। देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक और न्यायिक दिशाएँ भी उनपर ही निर्भर करती है।
- इस परिप्रेक्ष्य में लीगल लिट्रेसी क्लब की स्थापना बच्चों की सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। यह उन्हें उनके अधिकारों एवं दायित्वों के साथ-साथ संविधान में निहित प्रावधानों का भी जानकारी सुलभ होगा।
- जहाँ तक बालिका शिक्षा की बात है कहा गया है कि एक बालक पढ़ता है तो वह शिक्षित होता है लेकिन एक बालिका पढ़ती है तो पूरा परिवार एवं समाज शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हेतु समाज का विशेष दायित्व है जिसपर होने वाले निवेश हमेशा पीढ़ियों तक लाभदायक होगा।
- प्रत्येक लीगल लिट्रेसी क्लब में उपलब्ध किताबों में 250 सेट किताब की व्यवस्था की गई है। यह बच्चों के हित में उठाया गया एक व्यापक कदम कहा जा सकता है। लीगल लिट्रेसी स्कीम के अन्तर्गत कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को कानूनी जानकारी देने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है।
- राज्य सरकार के सम्बंधित विभाग द्वारा सभी स्कूलों में छात्रहित से संबंधित विषयों पर सदैव सजगता बरती जायेगी।

- हम तीव्रगति से विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन हमारे समक्ष ह्यूमन ट्रेफिकिंग, बालश्रम, बाल शोषण एक व्यापक चुनौती के रूप में सामने है। सरकार के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सौजन्य से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि बच्चे जो हमारे राष्ट्र के अमूल्य निधि हैं के विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दें। साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करें।
- हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में जो अमूल्य योगदान दिये थे सभी एडवोकेट थे। जस्टिस थे। महात्मा गाँधी जी एडवोकेट थे। उनके बारे में कहा जाता है कि बिना खड्ग और ढाल के देश को आजाद कर दिया। उनके पास गोली नहीं था, बंदूक नहीं था लेकिन उनके पास कानून था। कानून का ज्ञान था। संवैधानिक ज्ञान था इसी ज्ञान से उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया।
- मैं जस्टिस पटेल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि बच्चों को कानून पढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल में लिट्रेसी क्लब का स्थापना किया।
- लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें अपना राइट्स नहीं पता है। उन्हें पता नहीं है कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ?
- मैं चाहूँगी कि संविधान का प्रस्तावना बच्चों को हर किताब के प्रथम पृष्ठ में हो। जैसे हर एक को राष्ट्रगान पता है उसी तरह हरेक को संविधान का प्रिअम्बल पता होना चाहिए।
- संविधान केवल एक किताब नहीं है बल्कि यह देश के लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है तथा गुरुग्रंथ साहिब है। हमको हमारा संविधान कैसे जीना है यह सिखाता है। हिम्मत दिलाता है।
- हमलोगों को पता रहता है कि राइट्स क्या है पर हमें अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। राइट्स एवं ड्यूटीज एक दूसरे के पूरक हैं तथा हमें देश के कानून को जानना चाहिए।
- सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

SRI RAGHUBAR DAS, HON'BLE CHIEF MINISTER, JHARKHAND

- जस्टिस की जो प्रक्रिया है या फिर सरकार की जो बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो हमारे गरीब तबके को मिलनी चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए इस आधुनिक युग में, इस ज्ञान आधारित युग में, हमारा समाज भी Knowledge Based Society बने। इसलिए लीगल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं झालसा के टीम को बहुत बधाई देता हूँ।
- हमें कुछ बनने का सपना नहीं देखना, हमें कुछ करने का सपना देखना है। नियत साफ एवं लगन और मेहनत रहेगी तो पूरा ब्रह्माण्ड आपके साथ खड़ा होगा, आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए।
- हमने शिक्षा को प्राथमिकता दी है क्योंकि अगर राज्य को हमें बदलना है, अगर राज्य को हमें विकसित करता है, इस राज्य को शिक्षित हमें करना होगा। क्योंकि शिक्षा ही विकास का द्वार खोलता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं है, शिक्षा से ज्ञान आती है, ज्ञान से समझदारी आती है, और समझदारी से ईमानदारी आती है, जिसकी आज देश को जरूरत है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, की सिर्फ देने नौकरी वाली नहीं, उसके अंदर नैतिकता की शिक्षा होनी चाहिए, उसके अंदर अध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, उसके अंदर बौद्धिक शिक्षा होनी चाहिए, उसके अंदर आज के इस आधुनिक युग में कौशल विकास की भी शिक्षा होनी चाहिए।
- कानून बनी हुई है। लेकिन कानून का पालन या कानून की जानकारी हमारी ग्रामीण जनता को नहीं है। और यह जागरूकता नहीं होने के कारण है। लीगल लिटरेसी में जो लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है होगा इसमें बहुत ज्यादा काम करना होगा क्योंकि निर्दोष महिलाओं की हत्या हो रही है, डायन विषाही के नाम पर। ये समाज में आप देख रहे हैं, काफी विकृति आई है।
- कोई बच्ची को पढ़ाई में दिक्कत हो, सरकार आपके साथ है। खूब पढ़ो। क्योंकि, आज दुनिया, जिसके पास ज्ञान है, विशेषताओं का भंडार है उसी का दुनिया है, उसी का राज्य है, उसी का देश है।



- न्यायपालिका का भी हफ्ता में कम से कम एक चैनल हो जिसमें न्यायपालिका को लेकर जो भी जानकारी है उसको उस चैनल के माध्यम से जनता को मिले। समाज में जागरूकता करके हम एक सभ्य समाज, एक सभ्य भारत का निर्माण कर सकते हैं।
- आज के इस अवसर पर झारखण्ड की सभी बच्चियों और माता पिता से यह अनुरोध है कि बेटा और बेटी में फर्क न करें। 2016 Olympics में बेटियों ने इज्जत बचाई। आज किसी क्षेत्र में हमारी महिलाओं और बेटियाँ पुरुषों से कम नहीं हैं। इसलिए झारखण्ड के समस्त लोगों से अपील है बेटा-बेटी में फर्क मत करो, बेटा को भी पढ़ाओ, बेटी को भी पढ़ाओ।

HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA, JUDGE, SUPREME COURT OF INDIA

- मैं कोशिश करूँगा आप सब से हिन्दी में बात करने की।
- यह लीगल लिटरेसी क्लब है जहाँ हम आपको थोड़ी कानून की बारे में जानकारी देंगे तो आप वहाँ गाँव, पड़ोस में, साथी लोग के बीच में जानकारी देंगे। इससे आपको खुशी मिलेगा। Recreation is Pleasure. Recreation is happiness. Legal Literacy Club जिसके आप मेम्बर हैं यह आपको खुशी देगा क्योंकि आप अपना कर्तव्य करेंगे as member of the club. इसलिए जो भी आप में से मेंबर चुना जायेगा सो आपलोग नालसा के सालसा के देवदूत हो।
- स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि आसमां में परी रहती है। परी जिसको Angel बोलते हैं। आप जो क्लब के मेम्बर हैं वो हमलोग के लिए Angels हैं। क्योंकि नालसा का जो बात है वो आप दूसरी जगह में पहुँचाएंगें।
- आपने एक श्लोगन लिखा है इधर "to renounce practices derogatory to the dignity of women" सो बिल्कुल सही है।
- एक अमेरिकन थे 200 साल पहले उन्होंने पूरे अमेरिका को बताया कि वो देश सबसे बड़ा सभ्य देश है जो अपने औरतों का सम्मान करता है। अगर औरतो को सम्मान नहीं किया जाता है तो वह सभ्यता नहीं है।
- लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लोग कानून जानते हुए भी सबकुछ समझते हुए भी अगर लड़की होगा तो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अभी इस वास्ते स्कीम बनाया गया है।
- कानून की बातें आप अपने माता-पिता को बताइए। घर में बताइए। पड़ोस में बताइए।
- शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र के लिए विवाह करो क्योंकि जब तुम गुजर जाओगे तो वह पानी देगा। ये 'पुत्र' का अर्थ क्या है। 'पुत्र' का अर्थ क्या 'बेटा' होता है। 'पुत्र' का अर्थ 'बेटा' नहीं होता है। देखिए जब गाड़ी चलती है सुबह तो फिर दुपहर आता है। दुपहर के बाद शाम होती है। संध्या के बाद रात होती है। गाड़ी एक जगह पर नहीं रूकती। उसी तरह एक शब्द, एक लब्ज, एक अलफ़ाज



वो कभी रूकती नहीं है। उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जो ढाई हजार साल पहले 'पुत्र' का अर्थ 'बेटा' था, आज उसका अर्थ होना चाहिए 'संतान'। 'संतान' का मतलब 'बेटा' होता है और 'बेटी' भी होता है।

- अब्राहम लिंकन बहुत इलेक्शन लड़े हरेक इलेक्शन हारे पर 1860 में वह प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा जो वह जीते। लिंकन 1864 में गुजर गये। गुजर जाने से पहले उन्होंने slavery को बंद कर दिया।
- आपको परिश्रम करना पड़ेगा। भगवान ने हमको जो माइंड दिया है। जो ब्रेन दिया है वो ऐसे-तैसे नहीं है। उसको आप जैसे-जैसे करते जाओगे वह वैसे बनेगा।
- आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर ये सोचोगे कि मैं यह कर पाऊँगा, कर पाऊँगी तो आप जरूर करोगे।
- आज जिन बच्चों ने प्राइज लिया उनके मन में जरूर होगा कि मैं ये स्लोगन लिखूँगा तो प्राइज लूँगा और मैं ढंग से बोलूँगा, ढंग से करूँगा तो प्राइज लूँगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिनको प्राइज नहीं मिला उनमें जोश नहीं था उनमें भी जोश है।
- जर्मनी में ओलम्पिक हो रहा था। एक लड़का था 22 साल का। वह लौंग जंप में भाग ले रहा था उससे सही जंप नहीं हो रहा था वह लाइन क्रॉस कर जा रहा था। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम सोचो कि कहाँ लाइन है। तुम जंप करते हो 18 फीट पर तुम डिसक्वालिफाई हो जाते हो क्योंकि लाइन क्रॉस कर जाते हो। पहले सोचो कि लाइन कहाँ है उसके बाद जंप करो। उसने सोचा और जंप कर गया। इसलिए मेरा कहना है कि आप पहले सोचो और सोचने के बाद परिश्रम करो तो आप कामयाब होंगे।
- पहले माइंड में आ जाना चाहिए कि I am going to be successful. Once you think that you are going to be successful, nothing in this world can stop you.
- बच्चों लोग में यह भावना आनी चाहिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है। वह जो भी है बस आपके एक सपना आना चाहिए कि मेरा मौलिक कर्तव्य मेरा कर्तव्य है, मेरे भाई का कर्तव्य है, मेरे बहन का कर्तव्य है, मेरे दोस्त का कर्तव्य है, मेरे बंधु का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। यह एक-एक करके जब पिरामिड जैसा बन जाता है तो कर्तव्य स्थिरता आ जाता है और लीगल लिटरेसी क्लब का वही सम्बंध है आपको एक स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा रहना है मेरा बात आपको समझ आया तो अच्छा है और अगर नहीं समझ आया तो सोचना है।

HON'BLE MRS. JUSTICE R. BANUMATHI, JUDGE, SUPREME COURT OF INDIA

- I am very happy to participate in this inauguration of the Legal Literacy Clubs in the schools in the state of Jharkhand
- Do you know, when I was in school days, मैं तीन किलामिटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। प्रत्येक दिन ऐसा ही था Thereafter I and my two sisters went to Residential School stood successful and I came to this position. Therefore, if you all are in residential schools, there are many problems. Don't worry about problems. माता-पिता दूर है, भाई-बहन दूर है क्या प्रॉब्लम। Endure with success, then you will become very-very successful.
- If you endure like me, you will become Judges, you will become politicians, you will become minister. You will become very successful.
- Don't think that you are from ordinary background or village background. Many people who became successful were from village background. See the President of America Abraham Lincoln was very poor. He was from very ordinary background. But he became very-very successful and became very great President of America.
- You should not think ever about your ordinary background or village background. Always have your eyes on your future, then you will surely become successful.
- You can bring very much pride to your family, your village and your state.
- Most of you may be thinking what is this legal literacy. Do you know about Constitution of India. Constitution of India treats boys and girls as equals. There is absolutely no distinction between them. Constitution of India gives lots of protection not only in education but also reservation in both in employment and education everything. Therefore, you must know about your rights given in the Constitution of India.
- This Legal Literacy Club not only lets you know about the Constitution but you will who learn what are the rights available and what the duties. You will learn about the beneficial schemes. There are lots of scholarship scheme available for you. With Legal Literacy Club, you can know not only the rights under the law but also the benefits.
- Today I impress upon you to resolve to have a very-very high ambition to become a Judges a minister, a doctor, an engineer. I wish you a very-very bright future. After 10 years I would love to see you as teachers, doctors, lawyers, engineers. Today, you must resolve that today is the turning point of my life.
- Thank you for giving me this opportunity. I wish you a very-very bright future.



**HON'BLE MR. JUSTICE P.K. MOHANTY, CHIEF JUSTICE, HIGH COURT OF JHARKHAND
CUM PATRON-IN-CHIEF, JHALSA**

- I welcome you on this august occasion of opening of Legal Literacy Clubs.
- Rights of poors and rights of downtrodden are dependant upon Legal Services Authority and I am happy that Jharkhand State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee and other stake holders are working in a team spirit and helping the poor and needy to mitigate their grievances.
- On this auspicious occasion, I on behalf of legal services Authority express my gratitudes in the matter of spreading legal awareness amongst the children who are the future of the nation. The future of the country depends upon the children. Students of today are likely to lead the nation in future in its march for success.
- Students of the Legal Literacy Clubs has been assigned the duties to help those who are poor and ignorant of their rights and duties.
- It is the duty of the teacher in charge of the students Legal Literacy Club to facilitate the members to discharge their duties by distributing legal aid application form and door to door campaign.
- Being Patron in Chief, I once again express my sincere gratitude to Her Excellency the Hon'ble Governor of Jharkhand for extending all kind of support; I express my gratitude to Hon'ble Chief Minister of Jharkhand, Hon'ble HRD Minister and Chief Secretary. I further express my sincere gratitude to Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India who has always been a guide to us in organising such type of programme. I express my gratitude to Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, Judge, Supreme Court of India.
- Thank You once again to all.





**DR. NEERA YADAV,
HON'BLE MINISTER HRD DEPT. GOVT. OF JHARKHAND**

- आज का यह क्षण बहुत ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक नई दिशा की ओर जाने का प्रयास है। लिगल लिटरेसी क्लब की शुरूआत करने की बहुत जरूरत है
 - आए दिन देखते होंगे घरेलू हिंसा बच्चों को काम के बहाने बाहर ले जाना, बच्चियों को बेच देना, बाल विवाह, होटलों में बच्चों से कार्य कराना, ऐसे कई कारण हैं जिनका हम जानकारी के अभाव के कारण निजात नहीं पा सकते हैं।
 - झारखण्ड के लोगों को थोड़ा सा लोभ देकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। और बहकावे में आकर झारखण्ड की बेटी एवं बहने उन बिचौलियों के हाथों में चले जाते हैं और वहाँ से लौट नहीं पाते।
 - इस लिगल लिटरेसी क्लब का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इससे बच्चों को जानकारियाँ मिलेगी कि कैसे पढ़ाई के साथ-साथ अपने एवं आस-पास में, अपने परिवार को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएँगे।
- हमारी बेटियों को इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं जस्टिस दीपक मिश्रा और सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ।
 - यह क्लब बीच-बीच में बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रयास करेगा और यह 500 विद्यालयों ही नहीं बल्कि इसकी संख्या और आगे भी बढ़ाई जायेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।
 - अभी झारखंड राज्य में 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों सहित 500 विद्यालयों में Legal Literacy Club स्थापित किया जा रहा है।
 - मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि वे मन लगाकर के जब भी कोई प्रशिक्षण का कार्य हो तो उसे जरूर से सुनिये और उसका लाभ उठाईये। आपके जीवन को सफल बनाने में काफी मददगार होंगे। जिस प्रकार छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हो पायेंगी तो हमें लगता है एक आदर्श नागरिक बन करके देश के विकास एवं आदर्श समाज की स्थापना में अपना सक्रिय योगदान दे पायेंगी।

**HON'BLE MR. JUSTICE D.N. PATEL, JUDGE, HIGH COURT OF JHARKHAND
& EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA**

- जहां क्लब का शब्द आता है तो सबके मन में भाव आ जाता है Recreation का परन्तु हमलोग नालसा के 2010 के सर्कुलर के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जिसमें सभी State Legal Services Authority को High Schools एवं कॉलेजों में Legal Literacy Clubs खोलने का निर्देश दिया गया था।
- आजकल 11वीं कक्षा से ही Law (कानून) की पढ़ाई शुरू होती है।
- LLC में, Law की पढ़ाई व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। Law की पढ़ाई से सामाजिक न्याय क्या है मालूम होता है एवं सामाजिक मामलों की जानकारी होती है।
- हमलोगों ने छोटी-छोटी पुस्तिका बनवाई है जो LLC में रखी गई है 500 Schools में Govt. से छपवा कर रखा गया है जिसका आज अभी Inauguration होने वाला है। National Knowledge Committee ने भी ऐसा बोला है कि बच्चे स्कूल में भी Legal Education की पढ़ाई करें।
- मैं महामहिम का स्वागत करता हूँ, महामहिम सुबह से के कार्यक्रम में साथ हैं। वे सहर्ष ही इस कार्यक्रम में आने को राजी हो गई बल्कि उन्होंने कहा कि मैं एक-एक कर सभी 500 School में जाकर उद्घाटन करने के लिए राजी हूँ। हमारे राज्यपाल बच्चों में Law की पढ़ाई एवं ज्ञान के लिए बहुत संवेदनशील हैं।
She is always with the children.
- I welcome Hon'ble Justice Dipak Misra who love education and who is a man of untiring personality जो कभी थकते नहीं है।
- Hon'ble Minister Dr. Neera Yadav भी Tained Para Legal Volunteer रही है।
- हमलोग पाँच दिनों का P.L.V. Training करवाते हैं। हमारे पास कई Success Stories है।
- LLC में बच्चे सबसे अधिक ये पुस्तिका पढ़ें ये पुस्तिका आप घर पर भी ले जा सकते हैं घर पर पढ़कर अगल बगल के लोगों को भी पढ़ा सकते हैं।
- Government की तरफ से मुफ्त में छोटी-छोटी पुस्तिका दी गई है हमलोगों ने तय कर लिया है कि हर पन्द्रह दिनों में ये पाँच सौ स्कूल में कौन-कौन पढ़ाने जायेंगे। ये पढ़ाई का काम आधे घंटे से अधिक का नहीं होगा। ये आपका Subject नहीं है। पर आज कल law की पढ़ाई का Value है आज कल Lawyers का जमाना आ गया है। गांधी, जवाहर, बल्लभ भाई पटेल, Barak Obama का नाम सुना होगा। Lawyer can be a good politician also and lawyer can be judge also.



DISTRIBUTION OF CERTIFICATE & TROPHY OF COMMENDATION TO THE STUDENTS

of the schools of Jharkhand for Tribal Girls and Boys for their outstanding performance in essay competition, painting / drawing competition and slogan writing competition on **Fundamental Duties** as per NALSA guidelines. (This competition was organised in 500 schools amongst hundred of thousands of Girls and Boys in first week of December 2016



Her Excellency **Smt. Droupadi Murmu**, Hon'ble Governor Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Sri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister, Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble **Mr. Justice Dipak Misra**, Judge, Supreme Court of India giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble **Mrs. Justice R. Banumathi**, Judge, Supreme Court of India giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble **Mr. Justice P.K. Mohanty**, Acting Chief Justice, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Dr. Neera Yadav, Hon'ble Minister HRD Deptt., Govt. of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble **Mr. Justice D.N. Patel**, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Smt. Himani Pandey, Welfare Secretary, Govt. of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student

DISTRIBUTION OF CERTIFICATE & TROPHY OF COMMENDATION TO THE STUDENTS

of the schools of Jharkhand for Tribal Girls and Boys for their outstanding performance in essay competition, painting / drawing competition and slogan writing competition on **Fundamental Duties** as per NALSA guidelines. (This competition was organised in 500 schools amongst hundred of thousands of Girls and Boys in first week of December 2016)



Hon'ble Mr. Justice Aparesh Singh, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble Mr. Justice Pramath Patnaik, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble Mr. Justice Ratnaker Bhengra, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble Mr. Justice Ananda Sen, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble Mr. Justice S.N. Pathak, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Hon'ble Mr. Justice Rajesh Shankar, Judge, High Court of Jharkhand giving the certificate & trophy to the student



Madam Suprama Mishra & Madam Kalpana Mohanty



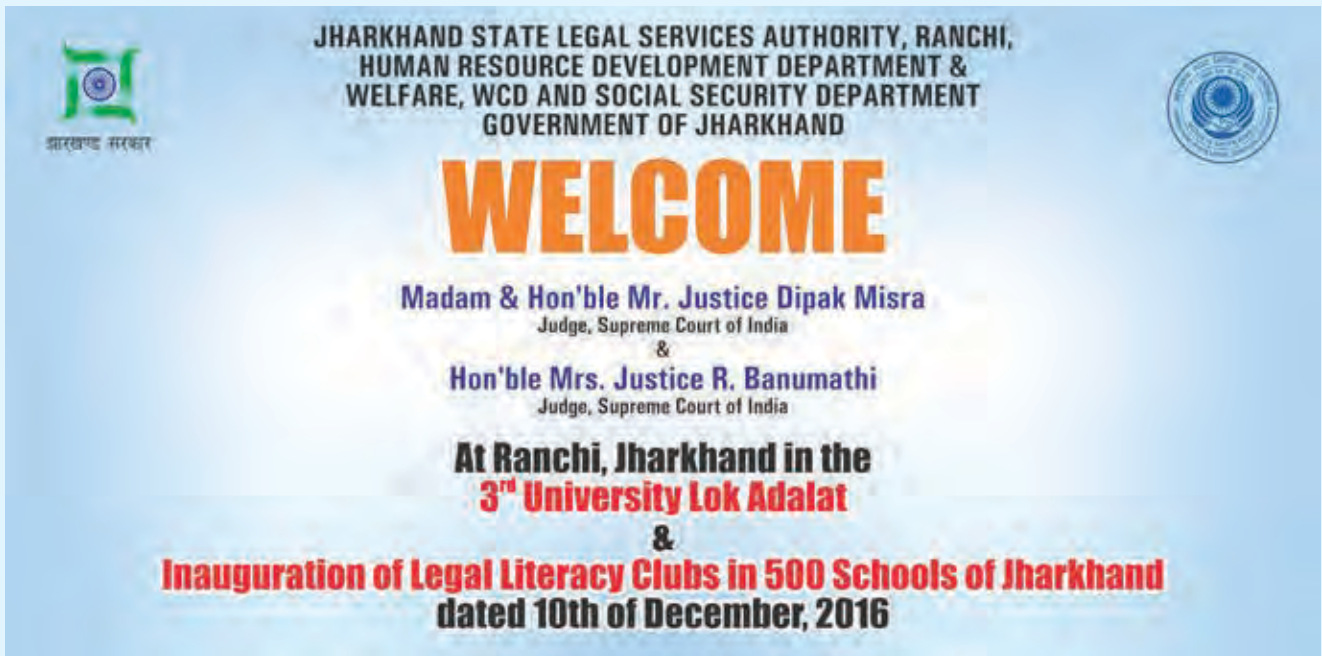
Madam Giraben D. Patel, Madam Sanchita Das, Madam Sweety Topno, Madam Poonam Mishra & Madam Vandana Singh



Welcome hoarding on the road



Arrival of Her Excellency Smt. Droupadi Murmu, Hon'ble Governor of Jharkhand, His Lordship Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India & Madam Suprama Misra at KGBV, Mandar



Welcome Hoarding installed at different places

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

BOKARO

1. K.G.B.V. CHANDANKIYARI
2. K.G.B.V. CHAS
3. K.G.B.V. KASMAR
4. K.G.B.V. PETARWAR
5. K.G.B.V. JARIDIH
6. K.G.B.V. BERMO
7. K.G.B.V. GOMIA
8. K.G.B.V. NAWADIH
9. RAMRUDRA +2 HIGH SCHOOL CHAS
10. KASMAR +2 HIGH SCHOOL KASMAR
11. SHARMIK HIGH TUPKADIH
12. PETARWAR +2 HIGH SCHOOL PETARWAR
13. NEHRU SAMARK HIGH SCHOOL SWANG
14. HIGH SCHOOL BANDHADIH
15. RAMRATAN HIGH SCHOOL DHORI
16. PROJECT GIRL HIGH SCHOOL PETARWAR
17. PROJECT GIRL HIGH SCHOOL TENUGHAT
18. RAMBILAS +2 HIGH SCHOOL BERMO
19. BHUSHAN +2 HIGH SCHOOL NAWADIH
20. HIGH SCHOOL DUGDA
21. GOVT. SC. RESIDENCIAL H.S. CHAS

WEST-SINGHBHUM, CHAIBASA

22. MARWARI +2 HIGH SCHOOL CHAKRADHARPUR
23. URDU TOWN HALL HIGH SCHOOL CHAKRADHARPUR
24. RASSEL +2 HIGH SCHOOL JAGANNATHPUR
25. LUPUNGGUTU +2 CHAIBASA
26. SPG GIRLS HIGH SCHOOL CHAIBASA
27. SPG BOYS HIGH SCHOOL CHAIBASA
28. SCOTT GIRLS HIGH SCHOOL CHAIBASA
29. ST. XEVIER GIRLS HIGH SCHOOL CHAIBASA
30. MANGILAL RUNGTA +2 HIGH SCHOOL CHAIBASA
31. LUTHERAN HIGH SCHOOL CHAIBASA
32. ZILA SCHOOL +2 CHAIBASA
33. MIDDLE SCHOOL BARAJAMDA AADARSH
34. KGBV BANDGAON
35. KGBV SADAR CHAIBASA
36. KGBV NOAMUNDI
37. KGBV SONUA

38. KGBV TANTNAGAR
39. KGBV JHINKPANI
40. KGBV TONTO
41. HIGH SCHOOL HATGAMHARIA
42. PADMAWATI JAIN SARSWATI VIDHYA MANDIR CHAIBASA
43. ST. XEVIER HIGH SCHOOL CHAIBASA
44. EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL TORSINDURI

CHATRA

45. RAJYA SAMPOSIT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATRA
46. GANGA SMARAK HIGH SCHOOL, GIDHOUR
47. JANTA HIGH SCHOOL, PATHALGADA
48. SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL, MAYURHAND
49. PROJECT BALIKA HIGH SCHOOL, HUNTERGANJ
50. PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL, ITKHORI
51. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, CHATRA
52. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, HUNTERGANJ
53. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, KUNDA
54. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, PRATAPPUR
55. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, LAWALONG
56. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, TANDWA
57. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, SIMARIYA
58. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, PATHALGADDA
59. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, ITKHORI
60. KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL GIRLS SCHOOL, GIDHOUR
61. SC RESIDENTIAL GIRLS HIGH SCHOOL, SIMARIA
62. NAJARATH VIDYA NIKETAN HIGH SCHOOL, CHATRA
63. INDUMATI TIBDEWAL SARASWATI VIDYA MANDIR, CHATRA
64. JAWAHAR NAVODAYA SCHOOL, CHATRA

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

DEOGHAR

65. K.G.B.V DEOGAHR
66. K.G.B.V DEVIPUR
67. K.G.B.V MOHANPUR
68. K.G.B.V MADHUPUR
69. K.G.B.V KAROWN
70. K.G.B.V SARATH
71. K.G.B.V SARWAN
72. K.G.B.V PALOJORI
73. RAJKIYAKRIT AWASHIYA VIDYALAY LERWA
74. M.L.G HIGH SCHOOL MADHUPUR
75. S.P.M HIGH SCHOOL MADHUPUR
76. ANCHI DEVI +2 SCHOOL MADHUPUR
77. SMT. ANARKARI +2 SCHOOL PALOJORI
78. MATRI MANDIR GIRLS HIGH SCHOOL DEOGHAR
79. R. MITRA +2 SCHOOL DEOGHAR
80. R.L SARRAF HIGH SCHOOL DEOGHAR
81. SRISRI MOHANANAND HIGH SCHOOL TAPOBAN
82. RANI MANDAKINI +2 SCHOOL KAROWN
83. R.B.J.P.SINGH +2 SCHOOL BAMANGAMA
84. HIGH SCHOOL, SONARITHARI

DHANBAD

85. S.S.L.L.N.T GIRLS +2 HIGH SCHOOL, DHANBAD
86. B.S.S. GIRLS HIGH SCHOOL, DHANBAD
87. UPGRADED HIGH SCHOOL, LOWADIH
88. K.G.B.V, JHARIA
89. JHARIA GUJRATI HINDI HIGH SCHOOL, JHARIA
90. JHARIA ACADEMY HIGH SCHOOL, JHARIA
91. T.A.P. +2 HIGH SCHOOL, TOPCHANCHI
92. K.G.B.V, TOPCHANCHI
93. +2 HIGH SCHOOL, GOVINDPUR
94. K.G.B.V. GOVINDPUR
95. MODEL SCHOOL, GOVINDPUR
96. PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL, GOVINDPUR
97. +2 HIGH SCHOOL, TUNDI
98. K.G.B.V. TUNDI
99. +2 HIGH SCHOOL, BALIYAPUR
100. K.G.B.V. BALIYAPUR
101. S.S.K.B.C. HIGH SCHOOL, NIRSA
102. K.G.B.V. SCHOOL, NIRSA

103. HIGH SCHOOL, KUMARDHUBI, DHANBAD
104. R.B.B. HIGH SCHOOL, RAJGANJ
105. G.N.M. HIGH SCHOOL, KATRASHGARH
106. D.P.L.M.A +2 HIGH SCHOOL, NAWAGARH
107. B.T.M. HIGH SCHOOL MALKERA, BAGHMARA
108. RESIDENTIAL HIGH SCHOOL, GOVINDPUR

DUMKA

109. ZILA SCHOOL, DUMKA
110. RK HS, DUMKA GIRLS
111. RK HS, KARHARBIL
112. NATIONAL HS, DUMKA
113. SRI RAM KRISHNA ASHRAM HS, DUMKA
114. KGBV, DUMKA
115. PROJECT HS, BARAPALASI, JAMA
116. KGBV, JAMA
117. RK HIGH SCHOOL, JARMUNDI
118. KGBV, JARMUNDI
119. KGBV, KATHIKUND
120. KGBV, MASLIYA
121. RK HS NONOHAT, RAMGARH
122. KGBV, RAMGARH
123. KGBV, RANESVAR
124. KGBV, GOPIKANDER
125. RK HS, HANSDIHA
126. KGBV, SARAIYAHAR
127. RK HS, SHIKARIPARA
128. KGBV, SHIKARIPARA
129. RK HS, SARAI DAHA
130. HIGH SCHOOL +2 SARAIYAHAT
131. HIGH SCHOOL +2 RAMGARH
132. HIGH SCHOOL +2 KATHIKUND
133. S.T. RESI. HIGH SCHOOL KARHALBIL
134. RESI. B.C. +2 HS KURUA DUMKA
135. EKLAVYA MODEL RES. SCHOOL KATHIJORIYA

GARHWA

136. R K GOVIND HIGH SCHOOL GARHWA
137. R K GIRLS HIGH SCHOOL GARHWA
138. R K RAMASAHU HIGH SCHOOL GARHWA
139. SHANTI NIWAS HIGH SCHOOL GARHWA
140. R K HIGH SCHOOL MERAL

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

- | | |
|---|---|
| 141. R K HIGH SCHOOL RANKA | 178. KGBV BIRNI |
| 142. R K HIGH SCHOOL RAMNA | 179. KGBV DEORI |
| 143. R K +2 HIGH SCHOOL NAGARUNTARI | 180. KGBV DHANWAR |
| 144. R K AMBALAL PATEL GIRLS HIGH SCHOOL NAGARUNTARI | 181. KGBV DUMRI |
| 145. PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL BHAWNATHPUR | 182. KGBV GANDEY |
| 146. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL GARHWA | 183. KGBV GAWAN |
| 147. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL MERAL | 184. KGBV GIRIDIH |
| 148. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL RAMNA | 185. KGBV JAMUA |
| 149. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL BHAWNATHPUR | 186. KGBV PIRTAND |
| 150. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL KANDI | 187. KGBV TISRI |
| 151. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL MANJHIAON | 188. HIGH SCHOOL RAMPUR GHORANGI |
| 152. KGBV GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL RANKA | 189. +2 HIGH SCHOOL, PALOUNGIYA |
| 153. GYAN NIKETAN SCHOOL GARHWA | 190. +2 HIGH SCHOOL, CHARGHARA |
| 154. B P DAV SCHOOL GARHWA | 191. MAHATMA GANDHI MIDDLE SCHOOL PACHAMA |
| 155. R K PUBLIC SCHOOL GARHWA | 192. SHARADA GIRLS MIDDLE SCHOOL, |
| 156. BNT ST. MARRY SCHOOL GARHWA | 193. NEHRU MIDDLE SCHOOL GIRIDIH |
| 157. R K +2 HIGH SCHOOL BHAWNATHPUR | 194. KAMLA NEHRU MIDDLE SCHOOL GIRIDIH |
| 158. R K HIGH SCHOOL CHITBISHRAM NAGARUNTARI | |
| 159. R K GOWAWAL HIGH SCHOOL DUMARIA | |
| GIRIDIH | |
| 160. +2 HIGH SCHOOL, GIRIDIH | 195. KGBV GODDA |
| 161. HIGH SCHOOL, MAKATPUR | 196. KGBV PATHARGAMA |
| 162. R.S.S.G.D.N, FANGEDIA GIRLS HIGH SCHOOL, PACHAMBA GIRIDIH | 197. KGBV MAHAGAMA |
| 163. SIR J.C. BOSS GIRLS HIGH SCHOOL, GIRIDIH | 198. KGBV BOARIJORE |
| 164. COALIYARI HIGH SCHOOL BANİYADIH | 199. KGBV SUNDERPAHARI |
| 165. +2 HIGH SCHOOL BENGABAD | 200. KGBV RAGHUNATHPUR |
| 166. +2 HIGH SCHOOL, GANDEY | 201. KGBV BALBADDA |
| 167. LANGTA BABA HIGH SCHOOL MIRZAGANJ | 202. KGBV THAKURGANGTI |
| 168. HIGH SCHOOL, TISRI BARMASIYA | 203. HIGH SCHOOL BASANTRAY |
| 169. HIGH SCHOOL, DHANWAR | 204. HIGH SCHOOL LALMATIA |
| 170. +2 HIGH SCHOOL, BAGODAR | 205. +2 HIGH SCHOOL BOARIJORE |
| 171. HIGH SCHOOL, SARIYA | 206. HIGH SCHOOL MOTIA |
| 172. GIRLS HIGH SCHOOL, SARIYA | 207. GIRLS HIGH SCHOOL GODDA |
| 173. +2 HIGH SCHOOL, DUMRI | 208. HIGH SCHOOL RAMLA |
| 174. HIGH SCHOOL, BHARAKATTA | 209. +2 HIGH SCHOOL GODDA |
| 175. PROJECT HIGH SCHOOL, DUMRI | 210. +2 HIGH SCHOOL MAHAGAMA |
| 176. KGBV BAGODAR | 211. GIRLS HIGH SCHOOL PATHARGAMA |
| 177. KGBV BENGABAD | 212. +2 HIGH SCHOOL PATHARGAMA |
| | 213. +2 HIGH SCHOOL POREYAHAT |
| | 214. HIGH SCHOOL MALMANDRO |
| | 215. +2 HIGH SCHOOL KHARKHODIA |
| | 216. +2 HIGH SCHOOL SUNDERPAHARI (BOYS) |

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

217. +2 HIGH SCHOOL DANRE

GUMLA

218. SS+ 2 HIGH SCHOOL, GUMLA
219. RK + 2 HIGH SCHOOL, BHARNO
220. SS+ 2 HIGH SCHOOL, GHAGARA
221. SS+ 2 HIGH SCHOOL, BISUNPUR
222. ST TULSIDAS +2 HS, SISAI
223. RK +2 HS, BASIA
224. KANDARP +2 HS, PALKOT
225. SS+2 HS, RAIDIH
226. RK +2 HS, DUMRI TANGARDIH
227. RK HS, MAGHI BALIKA HS, SISAI
228. RK HIGH SCHOOL, KARNJTOLI
229. SS GIRLS HIGH SCHOOL, GUMLA
230. KGBV, GUMLA
231. KGBV, SISAI
232. KGBV, BHARNO
233. KGBV, RAIDIH
234. KGBV, DUMRI
235. KGBV, GHAGHARA
236. KGBV, BISUNPUR
237. KGBV, PALKOT
238. KGBV, BASIA
239. KGBV, KAMDARA
240. ST IGNATIUS H S GUMLA
241. ST PATRIC H S GUMLA
242. URSULINE CONVENT GIRLS H S GUMLA
243. LUTHERAN HIGH SCHOOL GUMLA
244. RESIDENTIAL HIGH SCHOOL, GHAGHARA
245. ASHRAM HIGH SCHOOL, SISAI (TIRRA)

HAZARIBAGH

246. KGBV BARHI
247. KGBV BARKATHA
248. KGBV CHOUPARAN
249. KGBV PADMA
250. KGBV KATKAMSANDI
251. KGBV BARKAGAON
252. ANNADA HIGH SCHOOL, HAZARIBAGH
253. KGBV BISHNUGARH
254. GOVT. GIRLS +4 H.S., HAZARIBAGH

255. KBSS +2 H.S. CHOUPARAN, HAZARIBAGH

256. +2 HIGH SCHOOL BISHNUGARH
257. R.N. +2 H.S. PADMA
258. R.M. PROJ. H.S. CHANDA, ICHAK
259. PROJ. H.S. CHARHI
260. ST. ROBERT H.S. HAZARIBAGH
261. YADUNATH GIRLS H.S., HAZARIBAGH
262. CARMEL GIRLS H.S. HAZARIBAGH
263. ST. KIRAN GIRLS H.S., HAZARIBAGH
264. HAZARIBAGH HIGH SCHOOL, HAZARIBAGH
265. ST. COLUMBA'S COLLEGIATE SCHOOL,
HAZARIBAGH
266. OBC RESIDENTIAL GIRLS H.S., HAZARIBAGH
267. SC RESIDENTIAL H.S., BARSOT, BARHI,
HAZARIBAGH

JAMSHEDPUR

268. BPM +2 HS, BARMAMAINS
269. JAMSHEDPUR GIRLS HS, JAMSHEDPUR
270. PEOPLES ACADEMY HS, NEW BARADWARI
271. AMAR JYOTI HS, PARDIH
272. ST. MERRY HINDI HS, BISTUPUR
273. ST. JOSEPH HS, GOLMURI
274. ST. ROBERT HS, PARSUDIHI
275. SAKCHI HS, SAKCHI
276. LADY INDERSINGH GIRLS HS, INDERNAGAR
277. GURU NANAK HS, SAKCHI
278. BHARAT SEWA ASHRAM SANGH, HS, SONARI
279. JC HIGH SCHOOL, GHANTSHILA
280. KGBV, JAMSEDPUR
281. KGBV, MUSABANI
282. KGBV, DHALBUMGARH
283. KGBV, POTKA
284. KGBV, CHAKULIA
285. KGBV, PATMDA
286. KGBV, DUMARIYA
287. KGBV, GHANTSHILA
288. KGBV, BAHRAGORA
289. RESIDENTIAL BOYS HIGH SCHOOL,
UPPERPAWDA, GHANTSILA
290. RESIDENTIAL BOYS HIGH SCHOOL, SABARNAGAR,
POTKA

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

JAMTARA

291. J.B.C. +2 HS JAMTARA
292. RK GHS JAMTARA
293. PRO GHS MIHIJAM
294. KGBV JAMTARA
295. RK +2 HS, NARAYANPUR
296. KGBV NARAYANPUR
297. RK+2 HIGH SCHOOL, NALA
298. KGBV NALA
299. PROJ GHS KUNDAHIT
300. SB+2 SCHOOL KUNDAHIT
301. KGBV KUNDAHIT
302. RGRG HS KARMATANR
303. RK HS FATEHPUR
304. RESIDENTIAL HS DULADIH
305. SHARAM HS JAMTARA

KHUNTI

306. SS +2 HIGH SCHOOL KHUNTI
307. LAXMI NARAYAN+2 HIGH SCHOOL
308. +2 HIGH SCHOOL KARRA
309. AADIM JATI SEWA MANDAL HIGH SCHOOL
DUMARDAGA
310. JAYPAL SINH HIGH SCHOOL ALLUNDI
311. SS +2 HIGH SCHOOL RANIA
312. K B HIGH SCHOOL ARKI
313. K.G GIRLS SCHOOL KHUNTI
314. K.G GIRLS SCHOOL MURHU
315. K.G GIRLS SCHOOL KARRA
316. K.G GIRLS SCHOOL ARKI
317. K.G GIRLS SCHOOL RANIA
318. UPGRATED HIGH SCHOOL KALAMATI
319. UPGRATED HIGH SCHOOL TIRLA
320. UPGRATED HIGH SCHOOLGANALOYA
321. SCHEDUL TRIB BOARDING HIGH SCHOOL KUNDI
322. SCHEDUL TRIB BOARDING HIGH SCHOOL HUNT
323. BIRSA BOARDING SCHOOL ULIHATU ARKI

KODERMA

324. C. H. +2 HIGH SCHOOL, JHUMRI TILAIYA
325. C. D. GIRLS HIGH SCHOOL, JHUMRI TILAIYA
326. PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL, KODERMA

327. HIGH SCHOOL, KODERMA
328. SARVODAYA +2 HIGH SCHOOL, MARKACHO
329. K. G. B. V. MARKACHO
330. C. M. HIGH SCHOOL, DOMCHANCH
331. R. M. M. M. +2 HIGH SCHOOL, CHANDWARA
332. PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL, JAINAGAR
333. +2 HIGH SCHOOL JAINAGAR

LATEHAR

334. KASTURBA GANDHI AWASIYA BALIKA VIDYALAYA
335. KASTURBA GANDHI AWASIYA BALIKA VIDYALAYA
336. KASTURBA GANDHI AWASIYA BALIKA VIDYALAYA
337. KASTURBA GANDHI AWASIYA BALIKA VIDYALAYA
338. GOVT. HIGH SCHOOL, LATEHAR
339. GOVT. HIGH SCHOOL, CHANDWA
340. PROJECT HIGH SCHOOL, BARIYATU
341. SAINT TERESA GIRLS HIGH SCHOOL,
MAHUADANR
342. GOVT. HIGH SCHOOL BARWADIH
343. GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL CHANDWA
344. GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL LATEHAR
345. PROJECT HIGH SCHOOL CHHIPADOHAR

LOHARDAGGA

346. RESIDENTIAL MIDDLE SCHOOL FOR ST, KISKO
347. RESIDENTIAL MIDDLE SCHOOL FOR ST,
BAMANDIHA
348. RESIDENTIAL MIDDLE SCHOOL FOR ST,
LOHARDAGA
349. SS HIGH SCHOOL, KISKO
350. KASTURBA GANDHI GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL,
KISKO
351. PROJECT HIGH SCHOOL, KURU
352. KASTURBA GANDHI GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL,
KURU
353. KASTURBA GIRLS HIGH SCHOOL, LOHARDAGA
354. KASTURBA GANDHI GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL,
LOHARDAGA
355. KASTURBA GANDHI GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL,
SENHA
356. KASTURBA GANDHI GIRLS RESIDENTIAL SCHOOL,
BHANDRA
357. CHUNNI LAL HIGH SCHOOL, LOHARDAGA
358. HIGH SCHOOL BAMANDIHA, CHATTI

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

PAKUR

359. PAKUR RAJKIYA +2 HIGH SCHOOL PAKUR
360. HARINDANGA HIGH SCHOOL PAKUR
361. RANI JYOTIMARY GIRLS HIGH SCHOOL PAKUR
362. HIRANPUR +2 SCHOOL
363. LITTIPARA +2 SCHOOL
364. AMARAPARA+2 HIGH SCHOOL
365. MAHESPUR +2 HIGH SCHOOL
366. PAKURIA +2 HIGH SCHOOL
367. JIDATO GIRLS HIGH SCHOOL PAKUR
368. KGBV PAKUR.
369. KGBV HIRANPUR
370. KGBV LITTIPARA.
371. KGBV AMARAPARA
372. KGBV MAHESPUR
373. KGBV PAKURIA.
374. ST RESIDENTIAL HIGH SCHOOL,HIRANPUR.
375. PROJECT HIGH SCHOOL BARKIYARI, MAHESPUR
376. RAJKIYA HIGH SCHOOL BARTALLA, HIRANPUR

PALAMAU

377. GOVT. +2 HIGH SCHOOL , MEDININAGAR
378. GOVT. +2 GIRLS HIGH SCHOOL MEDININAGAR
379. GOVT. GIRIWAR HIGH SCHOOL MEDININAGAR
380. GOVT. BRAHMAN HIGH SCHOOL MEDININAGAR
381. GOVT. GLA HIGH SCHOOL MEDININAGAR
382. BCC MISSION GIRLS HIGH SCHOOL ABADGANJ
MEDININAGAR
383. GOVT. SRI SADGURU PRATAP HARI HIGH SCHOOL
CHAINPUR
384. GOVT. SARVODAY HIGH SCHOOL SATBARWA
385. GOVT. HIGH SCHOOL LESLIGANJ
386. GOVT. RAJYASAMPOSIT HIGH SCHOOL PANKI
387. GOVT. JANTA HIGH SCHOOL BISHRAMPUR
388. GOVT. JB HIGH SCHOOL REHLA
389. GOVT. KALYAN HIGH SCHOOL PANDU
390. GOVT. HIGH SCHOOL CHHATTARPUR
391. GOVT. SHITA HIGH SCHOOL HARIHARGANJ
392. GOVT. BAKSHI HIGH SCHOOL HUSSAINABAD
393. GOVT GIRLS HIGH SCHOOL HUSSAINABAD
394. GOVT. HIGH SCHOOL HAIDARNAGAR

395. KASTURBA G.B.V MEDININAGAR
396. KASTURBA G.B.V CHAINPUR
397. KASTURBA G.B.V. SATBARWA
398. KASTURBA G.B.V LESLIGANJ
399. KASTURBA G.B.V PANKI
400. KASTURBA G.B.V PATAN
401. KASTURBA G.B.V BISHRAMPUR
402. KASTURBA G.B.V PANDU
403. KASTURBA G.B.V CHHATTARPUR
404. KASTURBA G.B.V HARIHARGANJ
405. KASTURBA G.B.V HUSSAINABAD
406. UPGRADED HIGH SCHOOL KANDA NAWABAZAR
407. PICHRI JATEE AAWASHIYA VIDYALAYA SHAHPUR
408. ANUSUCHIT JAATE AWASHIYA VIDYALAY KAUWA
KHOH

RAMGARH

409. K.G.B.V RAMGARH
410. K.G.B.V PATRATU
411. K.G.B.V MANDU
412. K.G.B.V GOLA
413. S.S. HIGH SCHOOL GOLA
414. S.S. GIRLS HIGH SCHOOL RAMGARH
415. S.S. HIGH SCHOOL PATRATU
416. UHS HIGH SCHOOL BADKI KUNDRU
417. K.K.C. SAYAL BHURKUNDA PATRATU
418. SHARMIK HIGH SCHOOL TOPA
419. ST/SC SCHOOL MANDU

RANCHI

420. KGBV ANGARA
421. S S HIGH SCHOOL CHILDAG
422. S S HIGH SCHOOL BERO 10+2
423. KGBV BERO
424. PROJECT HIGH SCHOOL BERO BALIKA
425. KGBV BUNDU
426. KGBV BURMU
427. KGBV CHANHO
428. KGBV KANKE
429. GOVT HIGH SCHOOL BARIYATU BALIKA
430. ASTVS ZILA SCHOOL RANCHI
431. MARWARI +2 HIGH SCHOOL RANCHI

**LIST OF 500 SCHOOLS
OF STATE OF JHARKHAND WHERE 500 LEGAL LITERACY CLUBS WERE OPENED
AT A TIME ON 10 DECEMBER, 2016 FROM KGBV, MANDAR, RANCHI THROUGH
E-INAUGURATION**

432. KGBV LAPUNG
433. GOVT HIGH SCHOOL SOSAI
434. KGBV MANDER
435. KGBV NAMKUM
436. KGBV ORMANJHI/ANIL MISHRA
437. HIGH SCHOOL PREM MANJARI RATU
438. GOVT HIGH SCHOOL CHHOTANAGPUR RATU
439. KGBV SILLI
440. PROJECT HIGH SCHOOL TANGARBASLI BALIKA
441. KGBV SONAHATU
442. KGBV TAMAR
443. GOVT +2 HIGH SCHOOL BORIYA
444. PROJECT HIGH SCHOOL SILLI
445. CHOTANAGPUR GIRLS HIGH SCHOOL,
THARPAKNA RANCHI
446. S S HIGH SCHOOL 10+2, DORANDA, RANCHI
447. TVS HIGH SCHOOL, DHURWA, RANCHI
448. GAURIDATT MANDELIYA HIGH SCHOOL, RATU
449. BALKRISHNA HIGH SCHOOL RANCHI
450. K-B GIRLS HIGH SCHOOL, RATU
451. RESIDENTIAL HIGH SCHOOL, KAMRE
452. RESIDENTIAL +2 HIGH SCHOOL, JAIL ROAD,
RANCHI

SAHIBGANJ

453. KGBV BARHARWA
454. UPGRADED +2 BARHARWA. HIGH SCHOOL
455. KGBV BERHAIT
456. KGBV MANDRO
457. KGBV PATHNA
458. KGBV RAJMAHAL
459. HIGH SCHOOL , TINPAHAR
460. J.K. HIGH SCHOOL RAJMAHAL
461. KGBV UDHWA
462. UPG GOVT HS NAGARPALIKA KANYA
463. UPG INTER SCHOOL RAJSTHAN, SAHIBGANJ
464. YAMUNA DAS CHOUDHARY GIRLS HS
465. KGBV SAHIBGANJ
466. CENTRAL SCHOOL, SAHIBGANJ
467. JAWAHAR NAVODAY VIDYALAY SAHIBGANJ
468. ST. XEVIER'S HS HINDI, SAHIBGANJ

469. ST. XEVIER'S SCHOOL ENGLISH, SAHIBGANJ
470. KGBV TALJHARI

SERAIKELLA

471. KVPSDSS,GIRLS H.S.SERAIKELLA
472. WARSENI +2 H.S. SINNI
473. S.S.H.S. DALBHANGA
474. S.S.+2 H.S.,CHANDIL
475. PROJECT GIRLS H.S. KUCHAI
476. PROJECT GIRLS H.S. GAMHARIA
477. N.R. GOVT +2 H.S. SERAIKELLA
478. GOVT +2 H.S. KHARSAWAN
479. UTKRAMIT H.S.KALYANPUR
480. UTKRAMIT H.S.KOLABIRA
481. KASTURBA, KHARSAWAN
482. KASTURBA, NIMDIH
483. KASTURBA, RAJNAGAR
484. KASTURBA, GAMHARIA
485. KASTURBA,ICHAGARH
486. KASTURBA,CHANDIL
487. RESIDENTIAL BOYS H.S.SANJAY,SERAIKELLA
488. ASHRAM H.S. KUCHAI

SIMDEGA

489. SS +2 HIGH SCHOOL KOLEBIRA
490. SS +2 HIGH SCHOOL JALDEGA
491. SS +2 HIGH SCHOOL SIMDEGA
492. SS +2 HIGH SCHOOL BANO
493. SS +2 HIGH SCHOOL JORAM
494. KGBV SIMDEGA
495. KGBV JALDEGA
496. KGBV BANO
497. KGBV KOLEBIRA
498. KGBV THETHAITANGER
499. KGBV BOLBA
500. SS GIRLS HIGH SCHOOL SIMDEGA
501. GOVT HIGH SCHOOL BIRU
502. GOVT UPGRADED GIRLS HIGH SCHOOL
KOLEBIRA

LETTER OF JHALSA TO DLSAs FOR RESOURCE PERSONS FOR DECEMBER AND 1ST QUARTER 2016

Letter No.2744

dt 9-12-16

To,

The All the Principal District Judges cum Chairmen, DLSA, Except Pakur and Sahebganj

Sub: Online inauguration of Legal Literacy Clubs.

Sir,

As your goodself is well aware that 500 legal Literacy clubs in Govt schools are to be inaugurated on 10-12-16.

In this regard I have been directed by His Lordship Hon'ble Executive Chairman, JHALSA to request your goodselves to kindly be present in one of the schools with Deputy Commissioner, DEO and Supdt of Police of your judgship, as per list enclosed.

The timing of inauguration is from 3:00 PM.

Yours faithfully

Sd/-

(Arun Kumar Rai)

Member Secretary

Encl: As above

- Ranchi : 1. Govt High School, Sosai, 2. ASTVS Zila School
2. Deoghar: 1. KGBV, Kiro 2. Anchi Devi Saray Girls +2 HS, Madhupur, Deoghar
3. Jamtara: 1. RK Girls High school, 2. Project Girls High School Mihijam
4. Dhanbad : 1.KGBV, Nirsa, 2. KGBV, Jharia, 3.Jharia Gujarati Hindi HS
5. Gumla : 1.KGBV, Dumri, 2. Ursuline Convent
6. Jamshedpur: 1. Jamshedpur Girls High School 2. BPM +2 HS Barmamains
7. Khunti :+2 High School Karra
8. Giridih : KGBV, Giridih
9. Garhwa: KGBV Dumariya
10. Dumka : 1.Sri Ram Krishna Ashram HS, 2. Rk HS Dumka
11. Koderma : CD Girls High School, Jhumri Tilaiya
12. Chatra : 1. Jawahar Navodaya School, 2. SS Girls HS
13. Bokaro:+2 HS Dugda
14. Simdega: SS Girls HS
15. Hazaribagh: KBSS +2 HS
16. Godda: Govt +2 HS, Godda
17. Chaibasa: Scout Hindi Girls HS
18. Latehar: Project HS Bariyatu, Govt High School Barwadih
19. Lohardaga: KGBV, Kisko
20. Palamau: KGBS, Medininagar
21. Seraikella:1.KGBV Rajnagar, 2.SS +2 Chandel.
22. Ramgarh: SS Girls HS.

SUCCESS STORIES

BIRSA AGRICULTURAL UNIVERSITY, RANCHI

Matter related to payment of Pension and retirement benefits :

- 1) Late Milung Munda, Ex- Assistant, Ranchi Veterinary College expired suddenly on 06-08-2016. His dependents Sri Vijay Munda was to be paid Rs. 2,30,000/- as leave salary and salary due which was held up due to technical reasons for more than four months,- At the initiative of JHALSA this matter got settled in the LOK ADALAT and his dependents got the cheque of the required amount in the University Lok Adalat on 10-12-16.
- 2) Late Fransis Khalkho, Ex- Assistant, Biotech headquarter expired suddenly **on 28-12-2014**. His dependent **Srimati Pushpa Khalkho** was to be paid Rs. 4,76,703/- as leave salary and salary due which was held up due to technical reasons **for more than two years**. At the initiative of JHALSA this matter got settled in the LOK ADALAT and his dependents have got the cheque of the required amount.
- 3) Late Mahavir Baitha, Ex- Assistant, Estate Section (headquarter) expired **suddenly on 16-10-2015**. His dependent Srimati Lakshmi Devi **was to be paid Rs. 4,78,138/- as leave salary and salary due which was held up due to technical reasons** for more than twelve months. At the initiative of JHALSA this matter got settled in the LOK ADALAT and his **dependents have got the cheque of the required amount**.
- 4) Late Mahesh Prasad Singh , Ex- Assistant Professor, Forestry Department Sampada Section headquarter expired suddenly **on 26-01-2016**. His dependent **Srimati Meena Singh was to be paid Rs. 13,15,000/-** as leave salary and salary due which was held up due to technical reasons for more than ten months. At the initiative of JHALSA this matter got settled in the LOK . ADALAT and his **dependents have got the cheque of the required amount**.

Matter related to Appointment on Compassionate Ground

- 1) Late. Vijay Munda who was Field Overseer **expired while in service dn 03-05-2009**. His widow Srimati Geeta Devi could not be appointed in his place on compassionate grounds even **after 7 years** due to several technical, legal and administrative procedures pending. At the initiative of JHALSA the matter was re examined by the university and dependent Smt. Geeta Devi **got compassionate appointment** in the University Lok Adalat.
- 2) Late. Neori Oraon who was Lab Attendant expired while in service **on 29-05-2011**. His son Sri Vijay Oraon could not be appointed in his place on compassionate grounds even **after five years** due to several technical, legal and administrative procedures pending. At the initiative of JHALSA the matter was re examined by the university and dependent Sri Vijay Oraon **got compassionate appointment** in the University Lok Adalat.
- 3) Late. Basant Ram who was peon expired while in service **on 26-11-2011**. His son Sri Sudhir Kumar

could not be appointed in his place on compassionate grounds even **after five years** due to several technical, legal and administrative procedures pending. At the initiative of JHALSA the matter was re-examined by the university and dependent Sri Sudhir Kumar **got compassionate appointment** in the University Lok Adalat..

- 4) Late. Madho Toppo who was driver expired while in service **on 16-12-2011**. His son Sri Rameshwar Topo could not be appointed in his place on compassionate grounds even **after five years** due to several technical, legal and administrative procedures pending. At the initiative of JHALSA the matter was re-examined by the university and dependent Sri Rameshwar Topo **got compassionate appointment** in the University Lok Adalat.
- 5) Late. Shital Devi who was peon expired while in service **on 26-12-2012**. Her son Sri Anil Vikrant could not be appointed in her place on compassionate o grounds even **after four years** due to several technical, legal and administrative procedures pending. At the initiative of JHALSA the matter was re-examined by the university and dependent Sri Anil Vikrant **got compassionate appointment**.

Matter related to payment of Contractors

- 1) Sri Lalan Tiwari had executed the work of repair, maintenance and construction at KVK Palamu and Zonal Research Station Chianki under BAU control. The amount to be paid to the contractor was **Rs. 5,94,484.00 only but could not be paid due to technical reasons**. The petitioner also filed a **contempt case to recover this amount**. At the initiative of **JHALSA University Administration has paid the due amount to the contractor and the case is finally settled** in the University Lok Adalat.
- 2) Sri Ajit Kumar had executed the work of repair, modification and construction at KVK Latehar and RAC under BAU control. The amount to be paid to the contractor was **Rs. 9,14,232.00** only but could not be paid due to technical reasons. The petitioner also filed a **contempt case to recover this amount**. At the initiative of JHALSA University Administration has paid the due amount to the contractor and the **case is finally settled** in the University Lok Adalat.

KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA

Prof. A.A. Khan

Father Name: Late. Md. Ishaque Khan

Retired teacher of 5.8. College, Chandil.

Prof A.A. Khan retired teacher, Deptt. of History, 5.8. College, Chandil superannuated on July 2011. He gave his vital services for 38 year approx in the college. After effective initiative of the Hon'ble Lok Ada/at the arrear amount pending for a long time was released in favour of Prof A.A. Khan amounting to Rs. 2,65,801/- through cheque by Kolhan University, Chaibasa and save was paid to him in the University Lok Adalat.

Dr. Prof. Sahin Razi

Father Name: Mohamad Ussman

Retired teacher of Jamshedpur Women's College, Jamshedpur

Dr. Prof Sahin Razi retired teacher, Deptt. of Economics, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur superannuated **on 30.11.2016**. She gave her vital services for **38 year** approx in the college. After effective initiative of the Hon'ble Lok Ada/at the arrear amount pending for a long time was released in favour of Dr. Prof Sahin Razi amounting to **Rs. 2,82,802/-** through cheque by Kolhan University, Chaibasa in the University Lok Adalat.

Sri R. Dandpat

Father Name: Late. Vijeyendra Dandpat

Retired III grade employee of Mahila College Chaibasa

Sri R. Oandapat retired III grade employee of Mahila College, Chaibasa superannuated **31.05.2008**. He gave his vital services in the college. After effective initiative of the Hon'ble Lok Ada/at the arrear amount pending for a long time was released in favour of Sri R. Oandapat amounting to **Rs. 1,15,987/-** through cheque by Ko/han University, Chaibasa in the University Lok Adalat.

Sri Chandan Kumar

(Compassionate Appointment)

Late Kishor Prasad Singh ex-third grade employee of Jamshedpur Co-operative College, Jamshedpur expired in harness **on 18.04.2016**. His dependent son, Sri Chandan Kumar applied through the proper channel for appointment on compassionate ground. Acting on the effective initiative of the **Hon'ble Justice Sri D. N. Patel** of Lok Ada/at the University promptly convened the third meeting of the compassionate committee on 12.11.2016. In the meeting, the dire financial condition of the dependent family of the deceased was taken into account and in anticipation of the approval of the Syndicate the committee recommended for the appointment of Sri Chandan Kumar in third grade in the pay scale of 5200-20200 grade pay 1800 on a provisional basis. In compliance of the same the appointment letter of Sri Chandan Kumar was given in this Mega Lok Adalat.

RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Anup Tirkey S/o Sri Ram Oraon

A journey of success through intervention of JHALSA and Lok Adalat

Sri Ram Oraon started his service career to the post of peon **w.e.f. 14.9.81**. His services was absorbed w.e.f. 1.3.94. His pay fixation has also been approved by State Govt. in 6th revised pay scale in the pay scale of 4440-7440 + G.P. 1300/-. He died in harness on 22.6.14. Smt. Gangia Oraon W/o Late Ram Oraon vide her letter dated 3.11.14 had requested for appointment of her son Anup Tirkey on compassionate ground to look after her. The relevant documents relating to academic qualification were not submitted by Sri Anup Tirkey. In the meeting of compassionate committee held on 11.1.16, it was resolved to ask from Sri Tirkey to submit documents relating to his matriculation certificate or equivalent exams. In response to the University letter dated 25.2.2016. Sri Tirkdy submitted his relevant document on

30.9.16. **On intervention of JHALSA the matter was again** placed before the committee on 14.10.16 and recommendations were approved by the Syndicate vide Resolution no. 897 dated 15.10.16.

Finally appointment letter no. Esstt./EC/175116 dated 01.12.2016 has been prepared and delivered to Sri Anup Tirkey at Lok Adalat on 10.12.2016.

This fulfills his basic needs in place of his father.

Shashwat Arpan Nandy

A Journey of success through the intervention of JHALSA and Lok Adalat

Smt. Shushma Barobhaiya joined on 27.11.1981 as Lecturer in Botany at Ghatsila College, East Singhbhum on 17. 01.2007 she joined J.N. College, Dhurwa on transfer from Ghatsila College, Ghatsila. Smt. Barobhaiya expired on **30th July 2014**.

Sri Shashwat Arpan Nandy S/o Late Sushma Barobhaiya requested for appointment on compassionate ground as her mother was the only earning member in the family.

On intervention **of JHALSA his case was agam placed in the meeting** of compassionate committee held on 14.10.2016 and approved by the Ranchi University Syndicate vide resolution No. 897/16 dated 15.10.2016 for appointment on compassionate ground.

Finally on 10.12.2016 at 3rd University Lok Adalat the appointment letter was delivered to Sri Shashwat Arpan Nandy.

Dr. K.N. Gope

A Journey of success through the intervention of JHALSA and Lok Adalat

(16 year old dues paid in Lok Adalat)

The date of birth of Dr. K.N. Gope is 25.10.1939. Dr. Gope joined Ranchi University service on 05.10.1960 as L.D. Assistant, thereafter he promoted to U.D. Assistant, Head Assistant, Special Assistant and Assistant Registrar, Deputy Registrar. Dr. Gope worked on various administrative posts in Ranchi and Vinoba Bhave University as Deputy Registrar-1987, Development Officer-

1989, Controller of Examination - 1990 at Ranchi University. By order of Hon'ble Chancellor he was appointed as Registrar of Vinoba Bhave University, Hazaribagh in 1992. Dr. Gope was awarded Ph.D. Degree in 1995. Again Dr. Gope was appointed acting Registrar of Ranchi University in 1997. On 31.10.2001 he retired from the University service.

Due to non-approval of his pay fixation by the State Govt. to settle his retiral benefit he filed a writ petition followed by contempt case. However, on intervention of JHALSA his pay fixation has been approved by the State Govt. as also released arrear towards retiral benefits. Now his old disputes have finally been settled after 15 years of retirement and payment is being made for a sum of Rs. 10,24,019/- at 3rd University Lok Adalat held on 10.12.2016 by JHALSA.

Shri Vidya Nath Jha

A journey of success through intervention of JHALSA and Lok Adalat.

(Retiral dues paid in Lok Adalat after 4 years of retirement)

The date of birth of Shri V.N. Jha is 14.10.1952. Shri Vidya Nath Jha joined J.N. College, Dhurwa on 03.06.1972 as Office Clerk on 01.04.1978. He was promoted to the post of Assistant Librarian and as Librarian. On 31.10.2012 from Shri Vidya Nath Jha superannuated from the service of J.N. College, Dhurwa.

After retirement he was being paid only provisional pension on the basis of old pay scale. He was not paid his gratuity and leave encashment. His fixation of pay in new scale was pending before the Govt. for approval. Sri Jha filed a Writ Petition No. W.P.(S) 7560/2011 in the Hon'ble High Court, Jharkhand. After orders of the Hon'ble High Court his matter could not be cleared. Sri Jha filed a Contempt Case (C) No. 545/2012. This contempt case is referred to Lok Adalat by Hon'ble Justice D.N. Patel. By the intervention of JHALSA now the old dispute of fixation and payment of retiral benefit has finally been settled after 4 years of retirement and payment was made for a sum of Rs. 11,40,208/-.

Dr. Uma Shankar Sahu

A Journey of success through the intervention of JHALSA and Lok Adalat

(Dues paid after 32 years in Lok Adalat)

The date of birth of Sri Uma Shankar Sahu is 10.05.1947. Dr Sahu joined as Lecturer of Chemistry on 14.07.1971 at Tata College, Chaibasa on the recommendation of Bihar Public Service Commission. He was transferred from Tata College, Chaibasa to Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi in 1980. Dr. Sahu was promoted to the post of Reader in 1984. In 1987 he was promoted to the post of University Professor. In 1990 he was transferred to Ranchi College, Ranchi. Dr. Sahu superannuated from Ranchi University in 2009.

In spite of continuous attempts taken by Dr. Sahu to get the dues for the period 1984-1989 but he could not succeed. By the intervention of JHALSA now his old claims have finally been settled after 32 years and the payment of Rs. 8,45,506/- was made at Lok Adalat held on 10.12.2016.

NILAMBER-PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR, PALAMAU

प्रो० जगन्नाथ सिंह (1949-2015)

विलक्षण प्रतिभा के स्वामी प्रो० जगन्नाथ सिंह का जन्म बिहार के गाँव बेलाई, थाना-नब्बी नगर में हुआ। पिता राम केवल सिंह और माता कवलपति देवी ने जगन्नाथ सिंह को बचपन से ही अच्छे संस्कार और मानव मुल्यों की शिक्षा दी जो आगे चलकर उनके मानवीय और सामाजिक जीवन में परिलक्षित हुआ। इनके पिता और चाचा (श्री शालीग्राम सिंह) स्वतंत्रता सेनानी थे।

जगन्नाथ सिंह ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा नब्बी नगर और तेंदुआ (बिहार) से प्राप्त की पढ़ने-लिखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि पुनपुना नदी के किनारे किताबें लेकर घंटों पढ़ते रहते थे। समाचार पत्र के हर एक वाक्य को पढ़ लिया करते थे। आप मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर रहे। सन् 1964 में आपने पटना कॉलेज, (पटना विश्वविद्यालय) में आ. ए. में दाखिला

लिया बी0ए0 ऑनर्स और एम0ए0 मनोविज्ञान पटना विश्वविद्यालय से सन् 1970 में करने के उपरान्त आपने सन् 1972 में सिंह, कॉलेज विक्रमगंज, रोहतास बिहार में लेक्चरर के पद पर पढ़ना शुरू किया। आपने अपनी लगन और मेहनत से सिविल सर्विसेज कि लिखित परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। आपने सन् 1973 में “जनता शिवरात्रि महाविद्यालय, डालटनगंज (झारखण्ड) में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया और उसके पश्चात गणेशलाल अग्रवाल महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद को भी शुशोभित किया। आप नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात् **दिनांक 27.01.2015** को हृदय गति रूकने से आपका आकस्मिक निधन हो गया।

अबतक आपको विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति लाभ का पुरा नहीं हो पाया था प्रस्तुत तृतीय मेगा लोक अदालत के अवसर पर राज्य सरकार एवं झा0ल0सा0 के सहयोग से सेवानिवृत्ति लाभ के बकाए के भुगतान के रूप में रूपये 9,75,916 (नौ लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सोलह) का चेक-संख्या 028227, 028228, 028229- आपकी धर्मपत्नी श्रीमति प्रेमलता सिंह, को प्रदान किया गया।

डा0/श्री/प्रो0 **ब्यूला कच्छप**, योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज, डालटनगंज में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिनांक 18/02/1978 को दिया। अपनी सेवा के दौरान आपने महाविद्यालय के विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवम् संस्कृतिक गतिविधियों को जीवन्त एवम् गतिशील बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायी। आप शिक्षण कार्य के दौरान रीडर पद पर प्रोन्नति प्राप्त करते हुए नवसृजित नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर के अध्यक्ष छात्र कल्याण (D.S.W.) के पद से सेवानिवृत्त होकर राँची में निवास कर रही हैं।

तृतीय मेगा लोक अदालत के अवसर पर प्रिलिटिगेशन के तहत आपके छठे वेतनमान 33 प्रतिशत के बकाए राशि के रूप में लगभग छः साल बाद रूपये 59,138=00 की राशि का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है।

डा0/श्री/प्रो0 **श्रीमणी कुमारी**, योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज, डालटनगंज में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया। अपनी सेवा के दौरान आपने महाविद्यालय के विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवम् संस्कृतिक गतिविधियों को जीवन्त एवम् गतिशील बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायी। आप शिक्षण कार्य के दौरान रीडर पर प्रोन्नति प्राप्त करते हुए नवसृजित नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में अध्यक्ष पद पर सेवा के दौरान दिनांक **06-04-2015** को आपका आकस्मिक निधन हो गया।

तृतीय मेगा लोक अदालत के अवसर पर प्रिलिटिगेशन के तहत आपके छठे वेतनमान 33 प्रतिशत के बकाए राशि के रूप में लगभग छः साल बाद रूपये 4,14,980=00 की राशि का चेक आपके पति श्री शशिभूषण शर्मा को प्रदान किया गया।

डा0/श्री/प्रो0 **बी0 आर0 सहाय**, जी0एल0ए0 कॉलेज, डालटनगंज के अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया। अपनी सेवा के दौरान आपने महाविद्यालय के विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवम् संस्कृतिक गतिविधियों को जीवन्त एवम् गतिशील बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायी। शिक्षण कार्य के दौरान आपने पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की तथा अर्थशास्त्र की एक पुस्तक की भी रचना की।

जी0एल0ए0 कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के पद के साथ ही नवसृजित नी0 पी0 विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के आप प्रथम विभागाध्यक्ष भी रहे। **दिनांक 31/07/2010** को आप विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् सम्पति नी0 पी0 विश्वविद्यालय सेवा निवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं।

उच्च मेगा लोक अदालत के अवसर पर प्रिलिटिगेशन के तहत आपका सेवा निवृत्त लाभ 1,58,105=00 तथा 33

प्रतिशत छोटे वेतनमान के बकाये के रूप में 3,58,348=00 कुल रूपये 5,16,454=00 की राशि में से रू0 1,07,504=00 (TDS) घटाकर शेष राशि रूप 4,08,950=00 का चेक प्रदान किया गया।

डा0/श्री/प्रो0 **टी0एन0पी0 सिन्हा**, जी0 एल0 ए0 कॉलेज, डालटनगंज के इतिहास विभाग में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया। अपनी सेवा के दौरान आपने महाविद्यालय के विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवम् संस्कृतिक गतिविधियों को जीवन्त एवम् गतिशील बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायी। शिक्षण कार्य के दौरान आपने पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त।

नवसृजित नी0 पी0 विश्वविद्यालय के सी0सी0डी0सी0 के पद पर कार्य करते हुए आप दिनांक 31/08/2010 को आप विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

तृतीय मेगा लोक अदालत के अवसर पर प्रिलिटिगेशन के तहत आपके सेवा निवृत्त लाभ 1,62,978=00 तथा 33 प्रतिशत छोटे वेतनमान के बकाये के रूप में 3,58,934=00 कुल रूपये 5,21,912=00 की राशि में से रू0 1,07,680=00 (TDS) घटाकर शेष राशि रू0 4,14,232=00 का चेक प्रदान किया गया।

डा0/श्री/प्रो0 **सुरेंद्र प्रसाद वर्मा**, एस0एस0जे0एस0एन0 कॉलेज, गढ़वा के इतिहास विभाग में व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया। अपनी सेवा के दौरान आपने महाविद्यालय के विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवम् संस्कृतिक गतिविधियों को जिवन्त एवम् गतिशील बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायी। शिक्षण कार्य के दौरान आपने पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की।

एस0एस0जे0एस0एन0, कॉलेज, गढ़वा के प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26/03/2014 को आपका आकस्मिक निधन हो गया तृतीय मेगा लोक अदालत के अवसर पर प्रिलिटिगेशन के तहत आपके छोटे वेतनमान 33 प्रतिशत के बकाए राशि के रूप में लगभग छः साल बाद रूपये 98,276=00 की राशि का चेक आपके पुत्र श्री स्कन्द को प्रदान किया गया।

Litigation – WP(C) No. 4459 of 2014

नाम-कलावती शंकर, पता-प्रोपराइटर श्री मुद्रण, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू का नी0पी0 विश्वविद्यालय अन्तर्गत जी0एल0ए0 कॉलेज, मेदिनीनगर Stationary एवं अन्य सामग्री आपूर्ति के बकाए राशि के मद में 7,68,564 (सात लाख अरसठ हजार पाँच सौ चौंसठ) रूपये की राशि का भुगतान तृतीय मेगा लोक अदालत के माध्यम से कर उक्तवाद का निष्पादन परस्पर सहमति के आधार पर किया गया। चेक नं0 014823 दिनांक 19.11.2016 है।

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY

Arbind Chatterji, Retd. Teacher, Deoghar College, Deoghar

WP(S) No.-4345/05 was filed for promotion this promotion has been done. Pay fixation has been approved from higher and Technical Education Department. He is getting all financial benefits accordingly. This long standing problem has been solved completely in the 3rd Mega Lok Adalat.

Dr. Vinod Kumar, Retd. Teacher, A.S. College, Deoghar

WP(S) No.-1175/12 was filed for promotion in Reader. This promotion has been done and pay fixation has been approved by the Higher and Technical Education Department. He is getting all financial benefits.

3rd Mega Lok Adalat has helped him as the University took steps in the light of the direction given during meetings of 3rd Mega Lok Adalat and his problems have been solved completely.

Sri Murlidhar Upadhaya, Retd. Non-teaching Staff, K.K.M. College, Pakur

WP(S) No.-5416/08 was filed for his arrear claim. In the light of direction given in the meeting of 3rd Mega Lok Adalat Government has released fund and University paid his arrear in the 3rd Mega Lok Adalat.

Smt. Vimla Devi, W/o Late Basudeo Tiwary, Godda College, Godda

WP(S) No.-4524/13 was filed for retiral benefits of her husband Sri Basudeo Tiwari. In the light of the direction given during the meetings of 3rd Mega Lok Adalat, fund has been released by the Govt. and University paid all dues to her in the 3rd Mega Lok Adalat.

Sri Amar Nath Jha, Retd. Non-teaching Staff, S.P. College, Dumka

WP(S) No.-5375/13 was filed for pay fixation. Pay fixation has been done. In the light of the direction given during meetings of 3rd Mega Lok Adalat his remaining amount has been released and University paid all dues to her in the 3rd Mega Lok Adalat.

Sri Arun Kumar Jha, Clerk, P.G. Centre, Dumka

In the light of the direction given during the meetings of 3rd Mega Lok Adalat fund related to payment of Earned Leave of Retired Persons and SKMU, Dumka paid him in 3rd Mega Lok Adalat.

Smt. Flora Kisku, W/o Late Sri Noel Murmu, Clerk, P.G. Centre, Dumka

In the light of the direction given during the meetings of 3rd Mega Lok Adalat, fund has been released by the Government for payment of Earned Leave of Retired Persons and S.K.M. University, Dumka, University paid the amount in the 3rd Mega Lok Adalat.

Smt. Sima Murmu, W/o Late Prem Kisku, Peon, Deoghar College, Deoghar

In the light of the direction given during the meetings of 3rd Mega Lok Adalat, fund has been released by the Government for payment of Earned Leave of Retired Person and S.K.M. University, Dumka. University paid the amount in the 3rd Mega Lok Adalat.

Non-teaching employees, belonging to eight constituent colleges of SKM University, Dumka & 33% of teaching employees

In the light of the direction give during the meetings of 3rd Mega Lok Adalat, fund has been released for payment of difference of 6th pay of non-teachings of colleges. It was a long standing demand which has been solved and University paid them in 3rd Mega Lok Adalat. Similarly 33% salary arrear of Teachers

for the period of 1.1.2006 to 31.03.2010 has been released by the Government. The university paid the dues in 3rd Mega Lok Adalat on 10-12-16.

Compensate appointment

In the light of the direction given during meetings of 3rd Mega Lok Adalat sixteen appointment pending on compassionate ground have been done.

VINOBA BHAVE UNIVERSITY, HAZARIBAG

1. Arrears due to revision of salary to teachers in the 6th pay-scale was long due from 01.01.2006 to 31.03.2010 only 34% total due amount was released to teachers in the year 2015 and the payment of rest amount (66%) was pending. In the 3rd Lok Adalat payment of 33% amount was disbursed.
2. **Sri G.P. Sharma**- In response to the order of Hon'ble High Court (W.P.(S)No. 986 of 2005 and Contempt Case No. 332 of 2010) the services of Sri G.P. Sharma was regularized by the order of Chancellor of Universities of Jharkhand. An Amount of Rs. 29,43,750/- was paid in the 3rd Lok Adalat against the retiral benefits.
3. **Dr. P.P. Verma** served V.B.U. as Registrar during the period from 02.09.2000 to 31.01.2003. Earlier he served Ranchi University as Inspector of Colleges. He retired from the service on 31.01.2003. He was getting his pension in the IVth pay-scale due to non approval of pay fixation in the Vth pay-scale from the HTE, Govt. of Jharkhand. He filed a writ petition to Hon'ble High Court (W.P.(S) No. 2479/2010). Consequent upon the order of the Hon'ble Court, a sum of Rs. 21,75,542/- has been released by the HTE and the same was paid in the Lok-Adalat on 10-12-16.
4. **Dr. Binod Shankar**-Annual increment due to non-Ph.D was stopped by the order of HTE. The order of HTE was quashed by Hon'ble High Court of Jharkhand (W.P.(S) No. 1650/2014). As a consequence of which his pension has been revised. The due differences was paid in the Lok Adalat on 10-12-16.
5. **Dr. Vanmala Choudhary** - She retired from K.B. Women's College, Hazaribag from the post of Head of the Dept. of Hindi on 31.03.2009. She had filed a W.P. (S) No. 3596/2004 for promotion to the rank of University Professor. She was promoted to the rank of University Professor with effect from 10.07.1992. She was running from pillar to post for getting the pecuniary dues on account of promotion and the retiral benefit. The Lok Adalat came to her as a boon because her claims have been settled down. Rs. 4,19,142/- and same was paid on 10-12-16.
6. Compassionate appointment-Appointment of Grade-III (01) & Grade IV (04) (total-05 persons) on compassionate ground has been processed at University level. The appointment letter was distributed in the 3rd Lok Adalat on 10-12-16.
7. Smt. Rupa Devi, VBU Hazaribag was a sweeper. Her claims of retiral due was fully paid in the Lok Adalat. Rs. 2,46,053/- was paid in Lok Adalat on 10-12-16.

8. The claim of Sri Kehar Singh, Night Guard of Ramgarh College has been cleared and same was paid in the Lok Adalat on 10-12-16.
9. The claim of arrear of Sri Niranjana Mahto, Peon at P.K. Roy Memorial College, Dhanbad was paid in the Lok Adalat on 10-12-16.
10. The case of arrear of Sri Harihar Nath Roy, Demonstrator at Sindri College, Sindri was also cleared and was paid in the Lok Adalat on 10-12-16.

JHALSA (LEGAL SERVICES FOR ERADICATION OF FEMALE FOETICIDE MENACE AND SAVING THE GIRL CHILD) SCHEME, 2016

“Civilization of a country is known by how it respects its women.”

Justice Dipak Misra

Background

“Let it be stated with certitude and without allowing any room for any kind of equivocation or ambiguity, the perception of any individual or group or organization or system treating a woman with inequity, indignity, inequality or any kind of discrimination is constitutionally impermissible. The historical perception has to be given a prompt burial. Female foeticide is conceived by the society that definitely includes the parents because of unethical perception of life and nonchalant attitude towards law. The society that treats man and woman with equal dignity shows the reflections of a progressive and civilized society. To think that a woman should think what a man or a society wants her to think is tantamounts to slaughtering her choice, and definitely a humiliating act. When freedom of free choice is allowed within constitutional and statutory parameters, others cannot determine the norms as that would amount to acting in derogation of law. Decrease in the sex ratio is a sign of colossal calamity and it cannot be allowed to happen. Concrete steps have to be taken to increase the same so that invited social disasters do not befall on the society. The present generation is expected to be responsible to the posterity and not to take such steps to sterilize the birth rate in violation of law. The societal perception has to be metamorphosed having respect to legal postulates.”

— Justice Dipak Misra

(Excerpts from order dt. 8.11. 2016
passed in Writ Petition (Civil) No. 349 of 2006)

Hon’ble Supreme Court of India has passed several directions in Writ Petition (Civil) 349/2006 (Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India & Ors. (Author-Hon’ble Mr. Justice Dipak Misra) for completely eradicating the menace of female foeticide and it is the Call of the Hour to root out this menace and everybody must know their duty and obligation in achieving the objective. The duty of legal fraternity in general and legal services fraternity in particular is to leave no stone unturned in ensuring compliance of Hon’ble Supreme Court’s order. This scheme aims to completely involve all the legal services work-force to ensure compliance of the Hon’ble Apex Court’s order in aforesaid case and discharge the duties expected from them in the orders.

Case No. - 349 of 2006
Order Dated 8-11-2016 (Author - Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra)
Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India

- (a) All the States and the Union Territories in India shall maintain a centralized database of civil registration records from all registration units so that information can be made available from the website regarding the number of boys and girls being born.
- (b) The information that shall be displayed on the website shall contain the birth information for each District, Municipality, Corporation or Gram Panchayat so that a visual comparison of boys and girls born can be immediately seen.
- (c) The statutory authorities if not constituted as envisaged under the Act shall be constituted forthwith and the competent authorities shall take steps for the reconstitution of the statutory bodies so that they can become immediately functional after expiry of the term. That apart, they shall meet regularly so that the provisions of the Act can be implemented in reality and the effectiveness of the legislation is felt and realized in the society.
- (d) The provisions contained in Sections 22 and 23 shall be strictly adhered to. Section 23(2) shall be duly complied with and it shall be reported by the authorities so that the State Medical Council takes necessary action after the intimation is given under the said provision. The Appropriate Authorities who have been appointed under Sections 17(1) and 17(2) shall be imparted periodical training to carry out the functions as required under various provisions of the Act.
- (e) If there has been violation of any of the provisions of the Act or the Rules, proper action has to be taken by the authorities under the Act so that the legally inapposite acts are immediately curbed.
- (f) The Courts which deal with the complaints under the Act shall be fast tracked and the concerned High Courts shall issue appropriate directions in that regard.
- (g) The judicial officers who are to deal with these cases under the Act shall be periodically imparted training in the Judicial Academies or Training Institutes, as the case may be, so that they can be sensitive and develop the requisite sensitivity as projected in the objects and reasons of the Act and its various provisions and in view of the need of the society.
- (h) The Director of Prosecution or, if the said post is not there, the Legal Remembrancer or the Law Secretary shall take stock of things with regard to the lodging of prosecution so that the purpose of the Act is subserved.
- (i) The Courts that deal with the complaints under the Act shall deal with the matters in promptitude and submit the quarterly report to the High Courts through the concerned Sessions and District Judge.
- (j) The learned Chief Justices of each of the High Courts in the country are requested to constitute a Committee of three Judges that can periodically oversee the progress of the cases.
- (k) The awareness campaigns with regard to the provisions of the Act as well as the social awareness shall be undertaken as per the direction No 9.8 in the order dated March 4, 2013 passed in Voluntary Health Association of Punjab (supra).

- (l) The State Legal Services Authorities of the States shall give emphasis on this campaign during the spread of legal aid and involve the para-legal volunteers.
- (m) The Union of India and the States shall see to it that appropriate directions are issued to the authorities of All India Radio and Doordarshan functioning in various States to give wide publicity pertaining to the saving of the girl child and the grave dangers the society shall face because of female foeticide.
- (n) All the appropriate authorities including the States and districts notified under the Act shall submit quarterly progress report to the Government of India through the State Government and maintain Form H for keeping the information of all registrations readily available as per sub-rule 6 of Rule 18A of the Rules.
- (o) The States and Union Territories shall implement the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Rules, 2014 forthwith considering that the training provided therein is imperative for realising the objects and purpose of this Act.
- (p) As the Union of India and some States framed incentive schemes for the girl child, the States that have not framed such schemes, may introduce such schemes.

Order Dated 20.01.2015 (Author - Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra)

Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India

- (i) The appropriate authorities under the Act who have been authorised to launch/initiate the prosecution shall be imparted training by the Judicial Academy of the High Court of Punjab and Haryana. During the training, the Director of Prosecution of the State shall remain personally present in the academy so that all the officers avail the training with all sincerity, concern and seriousness.
- (ii) The trials that are pending before various courts of the State, unless there is an interdiction by the High Court or by this Court, shall proceed with quite promptitude and be finalised within a period of four months commencing 1-2-2015.
- (iii) The State may think of appointing a panel of competent lawyers who can render proper assistance to the appropriate authorities for taking appropriate steps for every action under the Act so that eventually the action taken under the Act does not collapse due to technical flaws. This direction is given to have separate lawyers for prosecuting these causes as it requires a lot of technical knowledge and it is the obligation of the State to see that these kinds of maladies are eradicated. Unless eradicated in time, it has the potentiality to lead to a disorderly state of affairs. The State shall respond to the same by the next date.
- (iv) The Districts where the sex ratio is less, the Director of Prosecution and the Director of the Judicial Academy shall give adequate stress on their training so that authorities who are in charge of the said districts shall also rise to the occasion.
- (v) As has been stated in our earlier judgment i.e. Voluntary Health Assn. of Punjab v. Union of India, there has to be proper awareness camps which are to be organised by the State Legal Services Authority. It is required to be done. It shall issue directions to the District Legal Services Authorities throughout the State to hold awareness camps with a proper perspective so that the persons attending camps not only become aware of the legal consequences but also the societal and the

collective concern for sustenance of child sex ratio. And above all, the value of a life of woman, for she is the basic pillar of the human race in any society. If advised, the Patron-in-Chief of the State Legal Services Authority may constitute a separate cell for imparting such legal aid camps.

- (vi) We would request the learned Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana to fix a date for imparting training to the appropriate authorities and thereafter the Registrar (Judicial) shall communicate to the Chief Secretary of the State who shall see to it that all the appropriate authorities attend the training, failing which they will be liable for disciplinary proceedings.
- (vii) Mr Yadav, learned counsel for the State shall file a list of the cases which are pending in trial courts for trial before the Registry of this Court within 10 days hence. The Registry shall forward the same forthwith to the Registrar General of the High Court who, in turn, shall place the matter before the learned Chief Justice who is requested to issue a circular with a command that the cases shall be disposed of within four months.

Order Dated 04-03-2013 (Author - Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra)

Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India

- (i) It is the requisite of the present day that people are made aware that it is obligatory to treat the women with respect and dignity so that humanism in its conceptual essentiality remains alive. Each member of the society is required to develop a scientific temper in the modern context because that is the social need of the present.
- (ii) A cosmetic awareness campaign would never subserve the purpose. The authorities of the Government, the Non- Governmental Organisations and other volunteers are required to remember that there has to be awareness camps which are really effective. The people involved with the same must take it up as a service, a crusade. They must understand and accept that it is an art as well as a science and not simple arithmetic. It cannot take the colour of a routine speech. The awareness camps should not be founded on the theory of Euclidian geometry. It must engulf the concept of social vigilance with an analytical mind and radiate into the marrows of the society. If awareness campaigns are not appositely conducted, the needed guidance for the people would be without meaning and things shall fall apart and everyone would try to take shelter in cynical escapism.
- (iii) It is difficult to precisely state how an awareness camp is to be conducted. It will depend upon what kind and strata of people are being addressed to. The persons involved in such awareness campaign are required to equip themselves with constitutional concepts, culture, philosophy, religion, scriptural commands and injunctions, the mandate of the law as engrafted under the Act and above all the development of modern science. It needs no special emphasis to state that in awareness camps while the deterrent facets of law are required to be accentuated upon, simultaneously the desirability of law to be followed with spiritual obeisance, regard being had to the purpose of the Act, has to be stressed upon. The seemly synchronization shall bring the required effect. That apart, documentary films can be shown to highlight the need; and instill the idea in the mind of the public at large, for when mind becomes strong, mountains do melt.
- (iv) The people involved in the awareness campaigns should have boldness and courage. There should not be any iota of confusion or perplexity in their thought or action. They should treat it as a problem and think that a problem has to be understood in a proper manner to

afford a solution. They should bear in mind that they are required to change the mindset of the people, the grammar of the society and unacceptable beliefs inherent in the populace.

- (v) It should be clearly spelt out that female foeticide is the worst type of dehumanisation of the human race.

OBJECTIVES OF THE SCHEME

The main objects of the Scheme are:

- (i) To comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India passed in Writ Petition No. 349 of 2006 (Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India and Others) and ensure that the Legal Services Institution in the State of Jharkhand implements the directions of Hon'ble Supreme Court in letter and spirit.
- (ii) To effectively coordinate with other departments of the Government of Jharkhand for the compliance of the directions of the Hon'ble Supreme Court in aforesaid case in letter and spirit.
- (iii) To outline the basic rights of girl child to live, grow & prosper
- (iv) To create awareness in the local people about the provisions of PC&PNDT Act, 1994 in general and direction of Hon'ble Apex Court in Voluntary Health Association case referred to above in particular.
- (v) To create awareness about saving the girl child so that humanity and civilisation may be saved.
- (vi) To promote Gender Justice and Equality
- (vii) To ensure the benefit of Anganbadi, Mid day meal and right to free and compulsory education to the children in general and girl child in particular.
- (viii) To liaison with the Civil Surgeon office, District Administration and Police for strict vigilance on the functioning of Ultrasound Clinics/Facilities where sex foetus can be determined.
- (ix) To organise awareness programme at Community level i.e. to say Women, Sr. Citizen, Community etc. for eradication of Female Foeticide Menace
- (x) To undertake and organise training, Orientation and Sensitisation Programme for Civil Surgeon and his team members, District Administration and Police Administration for eradication of Female Foeticide.
- (xi) To undertake Research and Documentation to study sex ratio and girl child education ratio.
- (xii) The Legal Services Institution shall prepare a panel of competent lawyers who can render proper assistance to the appropriate authorities for taking appropriate steps for every action under the Act so that eventually the action taken under the Act does not collapse due to technical flaws. This direction is given to have separate lawyers for prosecuting these causes as it requires a lot of technical knowledge and it is the obligation of the State to see that these kinds of maladies are eradicated. Unless eradicated in time, it has the potentiality to lead to a disorderly state of affairs. The State shall respond to the same by the next date.

DATABASE

- a) JHALSA shall have database of the existing Central or State Schemes, policies, regulations, policy directives concerning Saving the Girl-Child and combating Female-Foeticide menace.
- b) JHALSA shall have database of the Registered Facilities where ultrasound machines are permitted for other purposes.
- c) The lists prepared shall be circulated annually to all the District Legal Services Authorities which shall further circulate the same to the Taluka Legal Services Committees, village panchayats, legal services clinics and PLVs.
- d) JHALSA shall also upload the list on its website.
- e) The pending cases shall also be uploaded on the Database.

Mechanism for Complaint/receiving Information

All complaints/Information may be given to JHALSA on its email-jhalsaranchi@gmail.com or at any legal services clinic run by JHALSA.

Legal Representation

- a) A competent panel of Lawyers and PLVs shall be prepared by each legal services institution.
- b) JHALSA and DLSAs shall ensure that the effective legal representation is available to the person initiating prosecution under the Act.
- c) Every District Legal Services Authority and Taluka Legal Services Committee shall designate at least one panel lawyer as Legal Services Officer for the purpose of this Scheme.
- d) The District Legal Services Authorities shall also depute sufficient number of PLVs for the implementation of this Scheme.
- e) The PLVs shall act as the interface between the legal aid seeker and the Legal Services Institutions.

Legal Services Clinic

- a) JHALSA shall open Legal Services Clinics in those districts/Areas where sex ratio is alarmingly low.
- b) The Legal Services Panel lawyers and Para Legal Volunteers deputed in those clinics shall be provided special training and they shall work on all seven days of a week in rotation to conduct awareness programme, Nukkad Natak and Road Shows.
- c) The Legal Services Clinics shall ensure that action is taken against hospitals/ clinics, where sex determination test is done or provisions of PC PNDT Act is violated.

Plan of Action

- a) JHALSA shall prepare the Pamphlets/leaflets containing important directions of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 349/2006 in Hindi/English/Local Language for disseminating information regarding the directions and ensuring compliance thereof.

- b) Legal Services to be provided would include informing the Governmental Bodies or Functionaries, Non-governmental organizations and other organizations to ensure that each and every direction of the Hon'ble Apex Court is complied and the objective of PC PNDT Act is achieved.
- c) JHALSA shall develop effective co-ordination and interface with all the stake-holders such as Civil Society, Government Departments, NGOs and Community Levels for promoting gender-justice, discouraging discrimination between girl and boy and ultimately ensuring that no incident of female foeticide takes place and no breach of law go unpunished.
- d) JHALSA shall effectively co-ordinate with the State Government to ensure that adequate manpower is always available for enquiry, search and prosecution.

Training and Orientation Programmes

- a) JHALSA shall conduct training and orientation programmes for panel lawyers and PLVs to sensitize them on how to deal with cases under this Act and to build their capacity, knowledge and skill. Sensitization programmes should also be organized for other stakeholders such as the government functionaries, police personnel, medical officers and NGOs.
- b) JHALSA shall, in coordination with the Jharkhand State Judicial Academy, plan and conduct training/ sensitization programmes for Judicial Officers with a view to ensuring timely Justice.



JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY'S SCHEME, 2016 FOR STUDENTS LEGAL LITERACY CLUBS IN THE SCHOOLS & COLLEGES

A. Objectives:

Children are supremely important national asset. It is the duty of every Civilization and Government to nurture the children and their childhood and provide an environment where they may grow to be fullest of their potential.

Child is the future citizen. He/She should be made aware of the laws of the land. Our Constitution provides for Fundamental Rights and Duties and our Children should know them at the earliest. With a view to inculcate legal knowledge, skill and aptitude, the concept of Students Legal Literacy Club has come in to being. These Student Legal Literacy Clubs together with Legal Cadet Corps Scheme will bring about the desired result and future generation will be fully aware with their legal rights and duties. Legal awareness means legal empowerment. Jharkhand State Legal Services Authority aims to establish strong and vibrant relationship with the students through these Legal Literacy Clubs.

B. Constitution:

In every High School and college in the State of Jharkhand, there shall be set up a Student Legal Literacy Club comprising selected students of Class-IX and above in schools and Second year and below in Colleges as members and the number of the members shall be not less than 10 and not exceeding 25. More than one club may be set up in a High School/College, if so required,. The Club shall run under the guidance of a teacher called "Teacher-in-Charge" to be nominated by the Headmaster/Principal. This club shall function in association with the In charge of Legal Cadet Corps of the School/College, in charge of National Service Scheme (NSS) and under the overall supervision of the Headmaster / Principal of the respective High School/College. A proforma regarding constitution of the club is at Appendix- 'A'. Each club shall bear an index number to be assigned by the Jharkhand State Legal Services Authority (here in after referred to as JHALSA). The School/College shall spare accommodation inside the school/college premises and SLSA shall ensure other required infrastructure for functioning of the Club in close co-ordination with the Education Department.

C. Legal Literacy classes for the Members of the Club:

There shall be organized at least one Legal Literacy Class in a fortnight in every high school/college where the Club has been established. The Judicial Officers (Sitting as well as Retired)/Advocates/Mediators/Police Officers & Forest Officers of the District Legal Services Authority/JHALSA will take those classes for briefing the members of the Club as well as the teacher in charge about the modus operandi of legal services by the SLSA, Pre-litigation settlements of disputes, Lok Adalats and ADR generally. Focus will be on the laws and welfare schemes of the Government relating to the women, Children, Labourers, people below the poverty line, or suffering from mental or physical disabilities and people otherwise remaining disadvantaged or marginalized in the society. The School/College Authorities shall extend due cooperation and logistic support to the SLSA in organization and conduct of those Legal Literacy Classes. The programme of such classes shall be chalked out by the SLSA at least one month before hand and intimated to the Headmaster /Principal of the concerned School to enable the latter to circulate the same among the members of the club as well as the Teachers in-charge. As far as practicable, these classes shall be organized on holidays or any working day

without any detriment to the conduct of the regular classes in the schools and without affecting the education of the member students. The JHALSA may consider payment of honorarium to the external resource persons who are engaged in the Legal Literacy Club.

D. Preparation and distribution of books and reading materials:

The JHALSA will prepare booklets, reading materials, leaflets, pamphlets etc. in local language with contents appropriate to the objective of the scheme and functioning of the club and cause distribution of the same to the members of the Clubs for the purpose of their self awareness and mass awareness. The JHALSA may take help of the State Government's different departments such as, Education, Health and Family Welfare, Social Welfare Development, Forest & Environment, Law, Labour & Employment and other departments, and may also take help of the Government of India's different departments as well as UNDP, UNFPA and other voluntary organizations to share with them the expenditure to be incurred in preparation of the materials and meeting the other expenditure. Those Government Departments and N.G.Os may also render help in providing these materials, or collaborate with the JHALSA in organizing and sponsoring different legal aid programmes under the scheme.

E. Functions & Activities of the Club:

The Primary function of the Student Legal Literacy Club is to Spread Legal Literacy and prepare the students for conducting awareness in their neighborhood and act as a bridge between the persons in need of Legal Services and JHALSA. The functions and activities of the clubs shall include the following:-

- a) To identify persons in their neighborhood who deserve legal aid or assistance and who are in need of protecting their rights conferred by law, and to refer those persons, with recommendation of the Teacher-in-Charge, to JHALSA or District Legal Services Authority for receiving Legal Aid.
- b) To distribute Legal Aid application forms free of cost to those who need legal assistance (these forms will be made available to the clubs at the instance of Legal Services Institutions).
- c) To spread legal literacy and awareness by setting up Rallies, making door-to-door visits in the neighboring areas, forming small groups of villagers for inter face, making Road shows, distributing leaflets, pamphlets, study materials etc. containing information regarding modus operandi of Legal Services, Pre-litigation settlement of disputes, Lok Adalat etc., various Government schemes on Poverty Alleviation, Health, Employment, and other social security measures.
- d) To observe important Days like World Environment Day, World Day against Child Labour, Women's Day, Disability Day, Mental Health Day, Children's Day, National Legal Services Day, Anti-Tobacco Day etc., and spread message in the public about the aim and object of those Days.

F. Maintenance of Registers:

The club shall maintain four separate Registers for the purposes as follows:-

- i) MEMBERSHIP REGISTER - to reflect the names of the Club members in every Academic year starting from 2016-17 onwards with signature of all the members as well as the name and signature of the Teacher-in-Charge. A copy of the entry in the Register for every Academic year shall be forwarded by the Teacher-in-Charge to the JHALSA through the respective Headmaster of the school within a fortnight after commencement of the Academic Session.

- ii) RESOLUTION REGISTER - to contain all the Resolutions passed by the Club with their respective dates, signature of the Teacher-in-Charge of the Club. Every such resolution should be countersigned by the Headmaster of the School.
- iii) ACTIVITIES REGISTER - to contain a brief description of the activities undertaken by the club with date, place, number of members participated etc. A brief report about the activities / programmes undertaken by the Club shall be sent by the Teacher-in-Charge to the JHALSA as soon as possible.
- iv) DESPATCH REGISTER - to reflect the letters and correspondences issued by the Club to different quarters. The Registers will be supplied to the Clubs by the JHALSA or its District units or the State Government. It shall be the duty of the Teacher-in-Charge to maintain those registers fairly and properly. Any officer of the JHALSA or DLSA , shall have power to inspect the Registers maintained by the Club.

G. Supervision, Evaluation & Cash Award:

The JHALSA shall exercise supervisory function over the activities of the Clubs operating in jurisdiction, maintain a separate register to reflect the details such as, members of the club, name of the Teacher-in-Charge, name of the Headmaster, brief mention of the activities undertaken or organized by the Club, number and details of the persons in need of legal services referred to by the individual clubs to SLSA, etc. The action taken report under the scheme shall be submitted to the JHALSA as per the proforma vide Appendix-B at the end of each month where-after the JHALSA may submit consolidated report in this respect to the National Legal Services Authority.

The JHALSA shall assess and evaluate the work done by the individual clubs and may institute cash award not exceeding Rs.10,000/- per year for the Best Legal Literacy Club, Rs 7500/- for the First Runner Up and Rs 5,000/- for the second runner up.

JHALSA shall give certificate and trophy to the Best Student at the School/College Level.

H. Extra Curricular Activities :

Jharkhand State Legal Services Authority shall make arrangement for Excursion Tours, Visits to Courts and other outdoor activities for the members of Legal Literacy Clubs. All expenditure shall be borne by the jharkhand State Legal services Authority. District level, Regional level and state level Seminars/ Workshops for the members shall be organized by JHALSA. At least one excursion tour in six months and one Seminar/Workshop in three months on the subjects relating to Children, Women, differently abled persons, Tribals and Poverty alleviation shall be organized. The members and teachers in charge of the Legal Literacy Clubs may be invited in the Seminars/Workshops organized by JHALSA at Ranchi from time to time and the travel /lodging/fooding expenses shall be borne by JHALSA.

I. Saving:

Notwithstanding anything contained herein before, the JHALSA shall have power to alter any of the provisions or to introduce any new provision in the scheme or to issue guidelines to supplement or complement to the existing provisions for the purpose of effective and efficient functioning of the Clubs in general or any particular Club.

Appendix A

STUDENTS LEGAL LITERACY CLUB JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

1. Name of the Club :
2. Date of Establishment :
3. Name of the School with details :
4. Name of the Headmaster :
5. Name of the Teacher-In-Charge :
6. Number of Members :

| S. No | Name of the Member(s) | Class and Section |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18] | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |

| S. No | Name of the Member(s) | Class and Section |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

Signature
Member Secretary JHALSA

Appendix B

Subject: - Action Taken Report in relation to Students Legal Literacy Club.

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

- (i) Month under Report :.....
- (ii) No. of programmes organized / activities undertaken by the Clubs. :.....
- (iii) No. of applications for Legal services referred by the Clubs to SLSA for legal assistance :.....
.....
- (iv) No. of applicants provided with legal aid / assistance by SLSA out of those as referred by the Clubs)
:.....

Please specify:

- a) Legal Aid provided :.....
- b) Legal Advice/ Counseling rendered:.....
- c) Disputes settled amicably on the basis of conciliation / Mediation.:.....
- (v) Other information if any:.....

Signature
Member Secretary, JHALSA

NAME AND ADDRESS OF THE CLUB:

CLUB INDEX : JHALSA/LLC/2016/ACTIVITIES REGISTER

| S.No | Date | Brief Description of the Activities Undertaken |
|------|------|--|
| | | |

Full Signature of the Teacher in Charge

NAME AND ADDRESS OF THE CLUB:

CLUB INDEX : JHALSA/LLC/2016/RESOLUTION REGISTER

| S.No | Date | Details of the Resolution Passed |
|------|------|----------------------------------|
| | | |

No. of Members present
Full Signature of the Teacher in Charge

NAME AND ADDRESS OF THE CLUB:

CLUB INDEX : JHALSA/LLC/2016/

MEMBERSHIP REGISTER OF THE CLUB

MEMBERS OF THE CLUB FOR THE YEAR 2016-17

Club Name:

Club Index: JHALSA/LLC/2016/

| S. No | Name of the member | Class and Section |
|-------|--------------------|-------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |

| S. No | Name of the member | Class and Section |
|-------|--------------------|-------------------|
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

Signature

No/Dated...../

Copy forwarded to the Member Secretary, Jharkhand State Legal Services Authority,

Full Signature of the Teacher in Charge

NAME AND ADDRESS OF THE CLUB:

CLUB INDEX : JHALSA/LLC/2016/

DESPATCH REGISTER OF THE CLUB



PAPER CLIPPINGS

Sunday Pioneer, 11, Dec, 2016

SC Judge wants boost to culture of settlement

University Lok Adalat addresses 5,537 cases at one go, likely to grab Limca Book of Records entry

SANJEEV JHA ■ RANCHI

Supreme Court Judge Justice Dipak Misra has appealed the judiciary fraternity to encourage and nurture the culture of settlement in the country.

Speaking at 3rd University Lok Adalat organised today which is likely to grab Limca Book of Records entry for number of cases to be addressed at one go, Misra said that the number of pendency of cases and nature of large

chunk of them clearly indicated that numerous cases could easily be addressed through settlement.

"Lok Adalat is a place where a common man is the protagonist and lawyer is only a facilitator. And we must keep in mind that whenever a case is addressed, what surfaces is not the victor or the looser, there emerges happiness, social stability and respect towards a system, said Misra. He added that events like Lok Adalat were need of the hour to strengthen social stability.

The 3rd University Lok Adalat organised by Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) for teaching and non-teaching employees of all the universities of the State is likely to get Limca Book of



Judge, Supreme Court of India, Justice Dipak Misra handing over a cheque to an employee during 3rd University Lok Adalat organised by Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) for teaching and non-teaching employees of all the universities of the State in Ranchi on Saturday. Jharkhand High Court Acting Chief Justice and JHALSA Patron-in-Chief Justice PK Mohanty and Judge Jharkhand High Court and Executive Chairman JHALSA Justice DN Patel are also seen in the picture. Vinay Murmu / Pioneer

Records entry for addressing as many as 5,537 cases at one go. A total of Rs. 113.58 crores were distributed among 4,910 beneficiaries in Lok Adalat.

The Adalat addressed cases pending since way back 1984-85 ranging from non-payment of pension, arrears, non-compliance to previous Pay Commission provisions and compassionate jobs in all the universities. At least 10 people received compassionate job offer letters which were under consideration for the last three-four years, mostly of Birsa Agricultural University (BAU).

Governor and ex-Officio Chancellor of all the universities in the State Droupadi Murmu, Chief Minister Raghubar Das, Supreme Court

Turn to Page 4

रांची एक्सप्रेस रांची, रविवार 11 दिसम्बर, 2016

तृतीय विश्वविद्यालय लोक अदालत का आयोजन

113.58 करोड़ की राशि का वितरण, 10 की अनुकंपा पर नियुक्ति

संवादकर्ता

रांची : भारतीय न्याय और न्याय विधि का एक अत्यंत बड़ा काम है विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए एक विश्वविद्यालयी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रांची में 113.58 करोड़ की राशि का वितरण किया गया और 10 की अनुकंपा पर नियुक्ति का काम भी पूरा हुआ।

चेहरे पर खुशी देखने आयाह ड : न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

न्याय विधान में बाधक न बनें : राज्यपाल



निर्णय-प्रतिपक्षों का समीकरण करने : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है।

नैतिक जागरण रांची, 11 दिसम्बर 2016

भूमि विवादों पर भी आयोजित हो लोक अदालत : राज्यपाल



राज्यपाल उज्वल न्यायराज्य में हरियाली का आयोजित कार्यक्रम में एक अनुकंपा पर नियुक्ति पर देते संवहर्ताजी सुधा दास।

- विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लोक अदालत
- कानूनी के सल्लाहकार का ध्यान रखें
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है।

राज्यपाल उज्वल न्यायराज्य में हरियाली का आयोजित कार्यक्रम में एक अनुकंपा पर नियुक्ति पर देते संवहर्ताजी सुधा दास।

निर्णय-प्रतिपक्षों का समीकरण करने : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है।

हाइकोर्ट परिसर में विश्वविद्यालय लोक अदालत, 10 की नौकरी 4910 को मिले 113 करोड़ रुपये

एक लेकर वर्षों से कार्यालयों के काम चल रहे लोगों के दिखले चेहरे लिटिगेंट्स पॉलिटी चम्पना राज्य की निम्नोच्ची : अरिंदम मिश्रा



लालफीताशाही न्याय की राह में बाधक : राज्यपाल

अनुकंपा पर राज्यपाल उज्वल न्याय में बाधक कि न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत को प्रोत्साहित किया है।

लोक अदालत में 5537 मामलों का निपटारा

सन्मार्ग

500 विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का ऑनलाइन शुभारंभ, राज्यपाल बोलीं कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास



श्री. अशोक मिश्रा

बाल के सदस्य दूसरो को करेगे जागरूक : जस्टिस मिश्रा

राज्यपाल श्री अशोक मिश्रा ने आज दोपहर 12 बजे के दौरान राज्यपाल भवन, रायचौरी में 500 विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्य दूसरों को जागरूक कर सकेंगे और समाज में न्याय की भावना फैला सकेंगे।

श्री अशोक मिश्रा ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्य दूसरों को जागरूक कर सकेंगे और समाज में न्याय की भावना फैला सकेंगे।

कानूनी ज्ञान के लिए भी हो एक चैनल: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्य दूसरों को जागरूक कर सकेंगे और समाज में न्याय की भावना फैला सकेंगे।

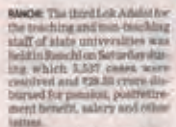
नेतृत्व सूची में रामन का समागम कटन-नेतृत्व

नेतृत्व सूची में रामन का समागम कटन-नेतृत्व। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

Lok Adalat for varsity staff clears 5,537 cases

ON-THE-SPOT SETTLEMENT ₹28.56 crore disbursed for pension, post-retirement benefit, salary and other issues

Gautam Muzumdar



Governor Druppalli Murmu lends over a cheque to a professor clearing her dues during the Lok Adalat on Saturday.

RAJAH: The third Lok Adalat for the teaching and non-teaching staff of state universities was held in Ranchi on Saturday evening which 5,537 cases were resolved and ₹28.56 crore disbursed for pension, post-retirement benefit, salary and other issues.

Later we also listed to 18 people for compensatory jobs. About 300 state legal services authority (JHALSA) claimed the Salary's Lok Adalat was the biggest one of the court settlement through Lok Adalat in the history of five state universities. The first of the series was held in 2013. About 30,000 from 1000s of Rs 1000s was present on the occasion.



Governor Druppalli Murmu lends over a cheque to a professor clearing her dues during the Lok Adalat on Saturday.

GOVERNOR URGES GOVERNMENT TO FIND AN ANSWER TO SOLVE RELUCTANCE OF THE PEOPLE TO GO TO THE POLICE STATIONS, HOSPITALS AND COURTS

Chief Minister Dr. Manmohan Singh said that the government should make a provision to solve the reluctance of the people to go to the police stations, hospitals and courts. He said that the government should make a provision to solve the reluctance of the people to go to the police stations, hospitals and courts.

Chief Minister Dr. Manmohan Singh said that the government should make a provision to solve the reluctance of the people to go to the police stations, hospitals and courts. He said that the government should make a provision to solve the reluctance of the people to go to the police stations, hospitals and courts.

तीसरे विश्वविद्यालय लोक अदालत में 4910 मामले निपटाए गए, 113.58 करोड़ के चेक का हुआ वितरण रिटायर्ड रीडर डॉ. उमाशंकर साहू को तीस साल की लड़ाई के बाद मिला प्रमोशन का बकाया पैसा

राज्यपाल श्री अशोक मिश्रा ने आज दोपहर 12 बजे के दौरान राज्यपाल भवन, रायचौरी में 500 विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्य दूसरों को जागरूक कर सकेंगे और समाज में न्याय की भावना फैला सकेंगे।

प्रभात खबर 11.12.2016

राज्यपाल श्री अशोक मिश्रा ने आज दोपहर 12 बजे के दौरान राज्यपाल भवन, रायचौरी में 500 विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

राज्यपाल लोक अदालत, 128.56 करोड़ का भुगतान, बोलीं राज्यपाल लोगों को उनके द्वार पर ही न्याय मिले

राज्यपाल श्री अशोक मिश्रा ने आज दोपहर 12 बजे के दौरान राज्यपाल भवन, रायचौरी में 500 विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि कानूनी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने परिवार और समाज के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

भूमि विवादों पर भी लगे लोक अदालत

लोक अदालत में 5537 मामले का निपटारा

400 5000

30 15-20

18

लोक अदालत में 5537 मामले का निपटारा

400 5000

30 15-20

18

लोक अदालत में 5537 मामले का निपटारा

400 5000

30 15-20

18

जस्टिस मिश्रा ने लाभार्थी से पूछा, भुगतान के लिए कब दिया आवेदन

तीसरी विधि लोक अदालत आयोजित, 4910 लोगों के घरों में खुशियां मनाने का दिन

संवाददाता

रांची : तीसरे विधि लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने लाभार्थी से इंतज़ार से पूछा कि क्यों को भुगतान के दिने किन्तु दिने पूर्व आवेदन दिने थे। उन्होंने इस सवाल पर अन्य लाभार्थियों से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्याय लोगों के दुख को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिये सम्बंधितों के पक्ष, डेन्यूटी समेत अन्य सुविधाओं में जुड़ी सम्बंधों का समाधान होता। उन्होंने इस क्षण को मानवता के दिने नव का निषण बताया। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कानून, इतना समेत सभी अधिकारों का प्रविण करण बमक है कि वे अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निपटार करते। इतर लोक अदालत से पांचों विधि के 4910 लाभार्थियों के घरों में दशम्वार का दिन खुशी मनानेका दिन लेकर आया। लोक अदालत में कई से अम्नी मांगों को लेकर भटक रहे लाभार्थियों के चेहरे पर संतोष का कब स्फट दिख रहा था। इन्कवट ज़ापन हाइकोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा।

मांडर में पांच सौ सड़कों में लीमन लिटरेसी क्लब का उद्घाटन। इतर लोक अदालत के बाद आज से राज के पंत सुकले में लीगल लिटरेसी क्लब का अड्डाकरण उद्घाटन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई न्यायाधीशों ने किया। इतने मात्र में एक साथ लीगल लिटरेसी क्लब खुलने को



लेकर कार्यक्रम में लिमन क्लब और कई रिजर्वों को ओर से अपनत निषेधो की दिखी से पहुंची थी। इन लाभार्थियों को फिली चक से राशि लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर बन्तुगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत अन्य न्यायाधीशों के हाथों पांचों विधि रांची विधि, विनोद भवे विधि, कोलहन विधि, सिद्धो-कानू विधि और नौलाकर-पोलावर विधि के श्रेष्ठिक और श्रेष्ठिक लाभार्थियों को बकाने राशि का चेक और निषुकि पत्र दिया गया। लाभार्थियों में रांची विधि के डा केरान मेघ और विद्यानप डा उम्पलेकर साठ, डा रेतन खलखो, डा जना कुमारी प्रसाद, डा मंजु कुमारी, कनीरव मिश्रा, आरता कुमारी, कतरवती शंकर, प्रमलता मिश्रा,

राशिभूषण शर्मा, मणु मोहंती, बेजला कच्छप, टीपीएन सिखा, डा बीआर साहा, एनके सिंह, नौलाकर-पोलावर विधि की डा इंदिरा सिंह, सुरेश मल्लो, सिद्धो-कानू विधि के अरविंद चटर्जी और अमरप्रभाब डा, विमल देवी, अलोक पंगरा, अरुण कुमारा डा, फोले किस्तु, नसीमा सुर्मा, गोकल चंद, सुजय कुमर सिंह, कोलहन विधि के उजज बीबी, एषा खन्ना और डा आरके मनुभदर शामिल हैं। ये श्रेष्ठ उपस्थित : कार्यक्रम में जस्टिस अजय सेन, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस एमनएन फडक, जस्टिस एजेश शंकर, मुख्य शिषि राजबाल राम, उच्च शिक्षा सचिव अरुण कुमार सिंह, महाविद्यालय विनोद, पोददार, अमर महावीरकला अशोक खाय, रांची विधि के वेसी रमेरा पांडेय समेत अन्य चर्चों विधि के बीबी, डीबीएँ डेके पांडेय

हमारी लोक अदालत विश्व में भी लोकप्रिय-राज्यपाल

कार्यक्रम में राज्यपाल द्रोपदी सुर्मा ने कहा कि देश की लोक अदालतों विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। इसके त्रिषे उन्होंने ज़ायला और हाइकोर्ट के न्यायाधीशों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहता है कि राज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके त्रिषे वे समय-समय पर चौथे समेत अन्य श्रेष्ठिक अधिकारियों के संग सम्मिका बैठक करती हैं। राज्यपाल ने राज में ज़ाहिन से जुड़े लोकप्रिय मामलों पर चिंत प्रकट किया। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय की दिता सभी को निषुकर काम करता होगा।

लोक अदालत से होती है समय व पैसे की बचत: जस्टिस पटेल

इलाहाबाद के अध्यक्ष जस्टिस दीपक पटेल ने कहा कि लोक अदालतों केवल आंकड़ों के त्रिषे नहीं बल्कि इससे अदालतों के प्रमर तथा आम लोगों के पैसे की बचत होती है। उन्होंने फाली और दूसरी लोक अदालत में निर्वाचित मामलों और लाभार्थियों के आंकड़ों को जानकारा दी। जस्टिस पटेल कार्यक्रम के त्रिषे राज्यपाल द्रोपदी सुर्मा और सीएम राहुल दास के प्रशंसा की समाहान की।

समते हाइकोर्ट के सैकड़ों अधिकार, शिक्षा विषय में जुड़े अधिकारों और लाभार्थी उपस्थित थे।

हाइकोर्ट परिसर में श्रेष्ठ सुस्थक के इंतज़ाम : लोक अदालत को लेकर गुर हाइकोर्ट परिसर में श्रेष्ठ सुस्थक के इंतज़ाम किए गये थे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के

स्पष्ट नीति से समस्याएं होंगी कम : सीएम

सीएम राहुल दास ने कहा कि राज्य में स्पष्ट नीति बनने से समस्याएं कम होंगी। उन्होंने कहा कि कठ समस्याएं एकीकृत बिहार के समाज को हैं। लेकिन उनका प्रयास है कि सरकर स्पष्ट नीति बनने, जिससे लोगों को कम परेशानी हो। उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ औरसत के मुकामले जीते रहने पर चिंत प्रकट किया। सीएम ने कहा कि सरकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। इस दिशा में शिक्षा विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रांची को उच्च आधुनिक राजधानी बदलेंगे। बी दास ने रांचीको दूर करने का सबसे बड़ा औरसत शिक्षा को बलगा। कार्यक्रम के त्रिषे सीएम ने ज़ायला को साधुवाद दिना।

आंकड़ों की नजर में तीसरी लोक अदालत

| | |
|-----------------------------|----------------|
| मुकदा पूर्व मामले | 1,83,577 |
| लक्षिक मामल | 14,660 |
| कुल निपटित मामले | 1,98,137 |
| कुल निपटित राशि | 1,20,84,71,876 |
| उपलब्ध करायी गई राशि | |
| रांची विधि | 33.04 करोड़ |
| रांची विधि | 1.10 करोड़ |
| विनोद भवे विधि | 02.70 करोड़ |
| कोलहन विधि | 10.30 करोड़ |
| सिद्धो-कानू विधि | 00.19 करोड़ |
| नौलाकर-पोलावर विधि | 03.26 करोड़ |

न्यायाधीशों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति के चलते इस क्षेत्र को वेद क्षेत्रों के सुस्थक लेकल से त्रिषुक्त कर दिता गव था।

आज - 11.12.16

500 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का शुभारंभ

मांडर (रांची), 10 दिसंबर। राज्य के 203 कस्बुएरा गांधी आवासीय विद्यालयों सहित कुल पांच सौ विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का आज आनलाईन उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल द्रोपदी सुर्मा, सीएम रघुवर दास, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आर आनुमति भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की शैक्षिक जानकारी को बढ़ाने के लिए इस क्लब की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से निरिषित तौर पर उनका सर्वांगीण विकास होगा।



कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व अन्य अतिथि। छाया : संजय

देश का संविधान भारतीयों के लिए गीता, कुरान और बाइबल की तरह ही है, जो हमें जीने की शालदिक्षाता

है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संविधान द्वारा लोगों को बहुत से

अधिकार दिए गए हैं। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में

लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इस दिशा में लीगल लिटरेसी क्लब मील का पत्थर साबित हो सकता है। शिक्षा केवल नौकरी वाली नहीं होगी चाहिए बल्कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। इस बार वजेट में 9वीं और दसवीं से ही बच्चों को स्कूल शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे भी स्मार्ट बनें। डायन-बिताही के नाम पर कई जगहों पर महिलाओं को गारा धा रहा है, इन सबसे शिक्षा का माध्यम से ही निवृत्ता जा सकता है। वर्तमान में नोटबंदी से परेशानी तो जरूर हुई है लेकिन हाथ पैसा वाली परंपरा जरूर समाप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा (श्रेष्ठ पृष्ठ 4 पर)

कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 500 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन

बच्चे शुरू से ही सीखेंगे कानून

संवाददाता

सांडर : झारखंड के राज्यपाल जेपी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, शिक्षामंत्री नीरा रायचंद व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने शनिवार को संयुक्त रूप से सांडर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 500 स्कूलों में शुरू किए जा रहे लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

सांडर महानगर राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी व 297 अन्य विद्यालयों में झालमा, स्कूलों शिक्षा व साक्षरता तथा कल्याण विभाग की अंतर्गत संचालित इस लीगल लिटरेसी क्लब के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल एवं स्वच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर. भानुमति, झारखंड हाइकोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस एल झालमा के संरक्षक पीके मोहंती, कार्यकारी अध्यक्ष, डीएन पीएल, मुख्य सचिव अहाधना भटनागरक, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय सहित झालमा, हालमा, हाइकोर्ट के कई अन्य व शिक्षा विभाग के कई अन्य अधिकारियों के अलावा विभिन्न



उद्घाटन करते राज्यपाल, प्रदेश एवं स्वच्छता मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एवं अन्य।

शिक्षा व जागरूकता से ही राज्य होगा विकसित: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड देश का एक राज्य है, जहाँ एक साथ पांच से अधिक स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का शुुरुआत की जा रही है। आज के इस ज्ञान आधारित युग में हमारा राज्य भी लीगल बेस्ट राज्य बने। बच्चे शुरू से ही कानून और अपने अधिकार व कर्तव्य को जाने यह क्लब उसी का एक कदम है। उन्होंने कहा कि अपने लिए सभी काम करते हैं। कल



मई दिना में जाने का एक सार्विक प्रयास है : शिक्षामंत्री

शिक्षा मंत्री नीरा रायचंद ने कहा कि यह नई दिशा में जाने का एक सार्विक प्रयास है। जनकारी के अभाव में बच्चे फाल हिमा, बाल व्यापार, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसी कई अन्य समस्याओं का निराकरण हो पाए है।

बच्चे आनंद पूर्ण वातावरण में कानून पढ़ेंगे : मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि लीगल लिटरेसी क्लब से बच्चे आनंद पूर्ण वातावरण में कानून पढ़ेंगे और हम उन्हें इसी वातावरण में उसकी जानकारी भी देंगे। क्लब के संस्थापक जस्टिस दीपक को तरह है जो कलमा को बात को सीखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे।

कठिनाइयों से परेशान नहीं हो : मानुमति

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर. भानुमति ने कहा कि जस्टिस परिसर से ही सफलता मिलती है। सफलता के लिए सफलता परिकर का होना ज़रूरी है।

कंपस

10.12.2016

पहल. हाइकोर्ट परिसर में शिक्षक-शिक्षकैतर कर्मियों के लिए लगेगी मेगा लोक अदालत

4910 मामलों पर आज होगा फैसला

रांची संवाददाता • रांची

रांची शिक्षा, कल्याण और सार्वजनिक शिक्षा मंत्री नीरा रायचंद ने कहा है कि लीगल परिसर लोक अदालत के जस्टिस राज्य के पांचों विधायकों के 4910 मामलों पर फैसला करेगा। जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा और शिक्षाकार कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की कति विवादों को सुलझेगा।

नेपाल सरकार के जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा मंत्री नीरा रायचंद ने कहा है कि लीगल परिसर लोक अदालत के जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा और शिक्षाकार कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की कति विवादों को सुलझेगा।

113.58 करोड़ रुपये का होगा वितरण

राज्य भर में काम कर रहे हैं पांच निजी विश्वविद्यालय : अजय सिंह

प्रत्येकी फैसला वाले विश्वविद्यालयों को अगले तीन वर्षों में अग्रण फैसला बना लेना है

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय के जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा मंत्री नीरा रायचंद ने कहा है कि लीगल परिसर लोक अदालत के जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा और शिक्षाकार कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की कति विवादों को सुलझेगा।

किस-किस विधि के कितने मामलों को होगा समाप

| विधि/विभाग | रकम/की संख्या | रकम/की संख्या |
|------------------------------|---------------|---------------|
| रांची विश्वविद्यालय | 1620 | 42.55 करोड़ |
| सिन्धुवा गांधी विश्व | 1321 | 36.67 करोड़ |
| रांची राज्य मुक्ति, दुमका | 1379 | 18.48 करोड़ |
| कोलार विश्व, कोलार | 584 | 12.54 करोड़ |
| कोलार-कोलार विश्व, मैदिनीपुर | 215 | 8.34 करोड़ |

विश्वविद्यालय को लेकर विवादों में लगे हुए हैं। इन पर अदालत फैसला करेगी। इनमें से 4910 मामलों पर फैसला करेगा। जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा और शिक्षाकार कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की कति विवादों को सुलझेगा।

यूनिवर्सिटी लोक अदालत में 128 करोड़ का होगा भुगतान : जस्टिस डीएन पटेल



यूनिवर्सिटी लोक अदालत में 128 करोड़ का होगा भुगतान : जस्टिस डीएन पटेल

जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि लीगल परिसर लोक अदालत के जस्टिस राज्य के जस्टिस शिक्षा और शिक्षाकार कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की कति विवादों को सुलझेगा।

3RD UNIVERSITY LOK ADALAT DATA

List of the Matter of Compassionate Appointment for 3rd University Lok Adalat

| SN. | University | Number of Cases |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Birsa Agriculture University | 10 (2 female + 8 male) |
| 2 | Sidhu Kanhu Murmu Univeristy | NIL |
| 3 | Ranchi University | 2 (both Male) |
| 4 | Kolhan University | 1 (Male) |
| 5 | Vinoba Bhave University | 5 (All male) (1 general + 2 SC + 2 ST) |
| 6 | Nilamber Pitamber Univeristy | NIL |

University wise total beneficiaries and amount

| SN. | University | Number of Cases | Total Amount |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Birsa Agriculture University | 743 | 15 Crore |
| 2 | Sidhu Kanhu Murmu Univeristy | 1370 (19 litigation matters) | 184753655/- |
| 3 | Ranchi University | 1620 (1 litigation matter) | 425518460/- |
| 4 | Kolhan University | 584 (1 litigation matter) | 125422918/- |
| 5 | Vinoba Bhave University | 1021 (7 litigation matters) | 366696143/- |
| 6 | Nilamber Pitamber Univeristy | 215 (1 litigation matter) | 34339587/- |
| | TOTAL | 5553 matters (44 litigation matters) | 1,286,730,763/- |

PROPOSED NEW BUILDING OF JHALSA



PRESENT JHALSA BUILDING



Prepared by

Jharkhand State Legal Services Authority

Nyaya Sadan, Near A.G. Office, Doranda, Ranchi

Phone : 0651-2481520, 2482392, Fax : 0651-2482397

Email : jhalsaranchi@gmail.com, Website : www.jhalsa.org

This Special Bulletin is also available on official website of JHALSA "www.jhalsa.org"